04 - देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता

05 - डेंगू, मलेरिया और जीका : खतरनाक कीट, वैश्विक संकट

A Daily News Magazine

भोपाल

बुधवार, 20 अगस्त, 2025

06 - कोई रचना कभी कोई फैसला नहीं देती

07 - स्वच्छता के प्रति जागरूकता और युवाओं के जज्बे को...

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 22, अंक 340, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

तमिलनाडु के 'अजातशत्रु' राधाकृष्णन पर बीजेपी क्यों लगा रही दांव?

शंकर अर्निमेष

महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन की जड़ें तमिलनाडु में हैं। उनकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रति 'निष्ठा' और दुश्मनों का न होना राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के लिए फायदेमंद साबित हुआ। रविवार को गठबंधन ने उन्हें 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार घोषित किया।

तमिलनाडु की सियासी गलियारों में जहां बीजेपी मतदाताओं को लुभाने में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है और जहां राधाकृष्णन कभी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें 'अजातशत्रु' (जिसका कोई शत्रु न हो) कहा जाता है। उन्हें 'कोयंबटूर का वाजपेयी' भी कहा जाता है, क्योंकि वे (अटल बिहारी) वाजपेयी युग के पुराने नेता रहे हैं। इतना ही नहीं, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम जैसे क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों के साथ बीजेपी के रिश्तों पर उनकी राय सबसे सम्मानित मानी जाती है।

राधाकृष्णन ने कई मौकों पर केंद्र सरकार का समर्थन किया है और तमिल पहचान के मुद्दे पर अपनी बात साफ शब्दों में रखी है।इसी साल मार्च में मुंबई में Hedgewar: A Definitive Biography नामक किताब के विमोचन के दौरान उन्होंने राज्य में भाषा विवाद पर बात की, जहां मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन 'हिंदी थोपने' का विरोध कर रहे थे।

उन्होंने कहा, 'तमिलनाडु में शब्द हथियार का काम करते हैं और अगर हम इसे और बांटते गए, तो यह ऐसा होगा जैसे शहर की बस में चढ़ने-उतरने के लिए पासपोर्ट दिखाना पड़े। यही हकीकत है।'

इसी तरह, 2023 में जब स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन धर्म पर टिप्पणी कर विवाद खड़ा किया, तब राधाकृष्णन ने सलेम में उन पर तंज कसते हुए कहा, 'कई मुगल बादशाहों ने सनातन को खत्म करने और हिंदुओं को मारने की कोशिश की। मुझे तो यह मज़ाकिया लगता है कि जो सनातन ऐसे हमलों से बच गया, उसे उदयनिधि मिटा देंगे।'

ऐसे में, बीजेपी के लिए राधाकृष्णन को देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद यानी उपराष्ट्रपति के लिए चुनना मुश्किल नहीं था। बीजेपी के एक पदाधिकारी ने कहा, 'पार्टी ने कई नामों पर विचार किया। साफ था कि नया उपराष्ट्रपति आरएसएस-बीजेपी कैडर से होगा, क्योंकि धनखड़ का प्रयोग अच्छा नहीं रहा था।'

बीजेपी के दूसरे नेता ने कहा, 'तमिलनाडु में पार्टी ने बहुत मेहनत की है। पुराने नेताओं के विरोध के बावजूद अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और इससे विस्तार हुआ। चुनाव से पहले एआईएडीएमके से तालमेल के लिए उन्हें बदला गया। राधाकृष्णन तमिलनाडु बीजेपी के सबसे सम्मानित चेहरों में हैं। उन्हें उपराष्ट्रपति बनाकर पार्टी ने तमिलनाडु और पूरे दक्षिण भारत को संदेश दिया है।' उन्होंने कहा, 'जैसे दो दशक पहले वेंकैया नायडू की नियुक्ति ने आंध्र और तेलंगाना में पार्टी को बढ़ाया, वैसे ही राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना तमिलनाडु में बीजेपी को ताकत देगा।'

बीजेपी के एक तीसरे नेता ने कहा, 'जाति और तमिल पहचान के अलावा उनकी नियुक्ति का बड़ा कारण प्रधानमंत्री से उनकी नज़दीकी और निष्ठा है।' प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एनडीए उम्मीदवार के तौर पर राधाकृष्णन का नाम घोषित करते हुए लिखा, 'सार्वजनिक जीवन के लंबे वर्षों में थिरु सी.पी. राधाकृष्णन जी ने समर्पण, विनम्रता और बुद्धिमत्ता से खुद को अलग पहचान दी है। उन्होंने हमेशा समाज सेवा और वंचितों को सशक्त बनाने पर ध्यान दिया है। तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर उन्होंने व्यापक काम किया है। मुझे खुशी है कि एनडीए परिवार ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना है।'

एनडीए के बहुमत को देखते हुए, यह तय माना जा रहा है कि राधाकृष्णन आसानी से उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। हालांकि, रविवार को संसदीय बोर्ड की बैठक में उनकी उम्मीदवारी ने राजस्थान, हरियाणा और गुजरात जैसे उत्तरी राज्यों से आने वाले कई दावेदारों को निराश किया। राधाकृष्णन, जो ओबीसी गोंडर समुदाय से आते हैं, उन्होंने 1973 में आरएसएस स्वयंसेवक के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी, जब स्वर्गीय सूर्यनारायण राव प्रचारक थे। एक साल बाद, वे भारतीय जनसंघ (जो बाद में बीजेपी बनी) की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बन गए। 1996 में उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का सचिव बनाया गया और 1998 में कोयंबटूर बम धमाकों के बाद पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। 1999 में वाजपेयी के समय और वेंकैया नायडू व राजनाथ सिंह की अध्यक्षता के दौरान वे दोबारा लोकसभा पहुंचे। 2004 से 2007 तक उन्होंने तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के रूप में काम किया। उनकी 1998 की चुनावी जीत एआईएडीएमके के साथ गठबंधन के दौरान हुई थी और 1999 की जीत डीएमके गठबंधन में। इसके बाद 2004 और 2014 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए।

राधाकृष्णन का एक अहम संगठनात्मक काम 19 हजार किलोमीटर लंबी रथयात्रा थी, जो 93 दिनों तक चली। इस यात्रा का मकसद था - सभी नदियों को जोड़ना, आतंकवाद खत्म करना, समान नागरिक संहिता लागू करना, अस्पृश्यता दूर करना और नशीली दवाओं की समस्या से निपटना। इसके अलावा उन्होंने अलग-अलग मुद्दों पर दो और पदयात्राएं निकालीं। उन्हें झारखंड, तेलंगाना का राज्यपाल और पुंडुचेरी का उपराज्यपाल बनाया गया।

झारखंड के राज्यपाल के अपने कार्यकाल में राधाकृष्णन ने पूरे राज्य का व्यापक दौरा किया, जिससे जेएमएम नेता हेमंत सोरेन असहज हो गए। महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आरएसएस संस्थापक हेडगेवार के प्रभाव को याद किया। इस साल मार्च में तमिलनाडु की भाषा विवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 'अलगाववादी ताकतें' तमिलनाडु और पंजाब में अब भी सक्रिय हैं, भले ही अलग-अलग तरीकों से।' हालांकि, अपनी बातों में राधाकृष्णन हमेशा सावधानी बरतते रहे हैं और कभी भी किसी लाल रेखा को पार नहीं किया।

सी.पी. राधाकृष्णन की एक बड़ी ताकत यह मानी जाती है कि उनके दोस्त डीएमके और एआईएडीएमके–दोनों पार्टियों में हैं। उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को लेकर डीएमके एक अजीब स्थिति में है। वजह यह है कि भले ही उन्होंने सनातन धर्म विवाद पर स्टालिन और उनके बेटे पर हमला बोला हो, लेकिन कई मौकों पर उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की भी तारीफ की है। बीजेपी द्वारा एक ओबीसी तमिल नेता को उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाना, ओबीसी समुदाय को एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने के रूप में भी देखा जा रहा है, खासकर पश्चिमी तमिलनाडु में। गोंडर समुदाय, जिसे राज्य की लगभग 10 प्रतिशत आबादी माना जाता है, चुनावों में एक मज़बूत ताकत है। एआईएडीएमके नेता एडाप्पडी पलानीस्वामी, जो राज्य में बीजेपी के साथ गठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं, गोंडर समुदाय से आते हैं और तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख अन्नामलाई भी इसी समुदाय से हैं।

'दिलचस्प बात यह है कि राधाकृष्णन जब भी वह दिल्ली जाते, तो हिंदी सीखने की क्लास ज़रूर लेते।'

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

झूठा निकला महाराष्ट्र में फर्जी चुनाव वाला दावा

- चुनाव विश्लेषक संजय कुमार ने खुद मांग ली माफी
- ...'वोट चोरी' के विपक्षी नैरेटिव को लगा बड़ा झटका

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकनीति-सीएसडीएस के चुनाव विश्लेषक संजय कुमार ने अपने एक झूठे डेटा के लिए माफी मांगी है। उन्होंने यह आंकड़े महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एक्स पर दिए थे। अपनी पोस्ट में उन्होंने एक्स (पहले ट्विटर) पर दावा किया था कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में उसी साल हुए लोकसभा चुनावों की तुलना में दो सीटों पर मतदाताओं की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई। अब संजय कुमार ने दावा किया है कि आंकड़ों की तुलना करने में उनकी टीम से चूक हो गई और उन्होंने दावे वाले अपने पुराने ट्वीट को डिलीट भी कर दिया है। लेकिन, उनके इस खुलासे से 'वोट चोरी' के विवाद पर मचा सियासी संग्राम और तूफानी हो गया है। संजय कुमार ने एक्स पर पोस्ट लिखा है, महाराष्ट्र चुनाव से जुड़े ट्वीट पर मैं सच में माफी मांगता हूं। 2024 के लोकसभा और 2024 के विधानसभा चुनावों के आंकड़ों की तुलना करने में चूक हो गई। पंक्ति में दिए गए आंकड़े हमारी डेटा टीम की ओर से गलत पढ़ा गया था। इसके बाद ट्वीट हटा दिया गया। गलत सूचना फैलाने का मेरा किसी भी तरह से कोई इरादा नहीं था। संजय लोकनीति-सीएसडीएस के को-डायरेक्टर हैं। लोकनीति-सीएसडीएस के चुनाव विश्लेषक का यह माफीनामा वाला ट्वीट आते ही बीजेपी भड़क गई है और वह यह कतई मानने को तैयार नहीं है कि 'सच में भूल' थी। बीजेपी आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने लिखा, माफी अंदर और संजय कुमार बाहर। संयोग से योगेंद्र यादव के इस व्यक्ति ने आखिरी बार कब कुछ सही कहा था। अपने हर अनुमानों में प्रत्येक चुनावों से पहले बीजेपी को हारते हुए दिखाया जाता है और लेकिन परिणाम उल्टा होता है।

राष्ट्रीय खेल प्रशासन का विधेयक बन गया कानून

राष्ट्रपति मुर्मू ने कर दिए इस पर हस्ताक्षर

नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के साथ ही राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक अधिनियम बन गया है। इस विधेयक में भारत के खेल प्रशासन में सुधार का वादा किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति की मंजूरी सोमवार को मिल गई। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि संसद के निम्नलिखित अधिनियम को 18 अगस्त, 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और इसे सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। खेल विधेयक एक दशक से अधिक समय से लंबित था। इसे पिछले एक वर्ष में विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद पारित किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक को 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया गया था और 11 अगस्त को इसे वहां पारित कर दिया गया। इससे एक दिन बाद राज्यसभा ने दो घंटे से अधिक समय तक चली चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया था।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुए मंत्रि-परिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को मंजूरी दी, कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव होगी

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफेक्चरिंग क्लस्टर्स (ईएमसी) 2.0 परियोजना अंतर्गत सामान्य सुविधाओं (सीएफसी) के साथ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन तथा विनिर्माण (ईएसडीएम) क्षेत्र के संवर्धन को बढ़ावा दिये जाने के लिए भोपाल की तहसील बैरसिया के ग्राम बांदीखेड़ी में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। परियोजना के लिए उपलब्ध 210.21 एकड़ भूमि पर परियोजना लागत 371 करोड़ 95 लाख रूपये की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गयी है। इसमें से राशि 146 करोड़ 63 लाख रूपये केन्द्रांश एवं 225 करोड़ 32 लाख रूपये राज्यांश होगा। भारत सरकार की प्राथमिकता के अनुसार डिजिटल इंडिया एवं मेक इन इंडिया की अवधारणा को साकार करने में ईएमएसी 2.0 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स (ईएमसी) योजना की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

ईएमसी 2.0 योजना, सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना में भी सहयोगी होगी। उन्हें ऐसे क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा, जहां बड़ी संख्या में मौजूदा विनिर्माण इकाइयां स्थित हैं, जिनके अंतर्गत सामान्य तकनीकी बुनियादी ढांचे के उन्नयन और ईएमसी, औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों/औद्योगिक गलियारों में इकाइयों के लिए सामान्य सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ईएमसी 2.0 परियोजना से इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा आधार तैयार होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम) क्षेत्र में नए निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। निर्माण इकाइयों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। निर्माण इकाईयों द्वारा भुगतान किए जाने के फलस्वरूप करों के रूप में शासकीय राजस्व में वृद्धि होगी। उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में मदद मिलेगी, साथ ही नवाचार को गति और देश के आर्थिक विकास को उत्प्रेरकता प्राप्त होगी।

मंत्रि-परिषद द्वारा नर्मदापुरम, मुरैना, बालाघाट, शहडोल और सागर में नवीन शासकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय और वैलनेस सेंटर खोलने के लिए 1570 पदों की स्वीकृति दी गई है। इनमें 715 नियमित पद एवं 855 पद आउटसोर्स के माध्यम से भरे जायेंगे। प्रदेश में संभाग स्तर पर एक आयुर्वेदिक मैडिकल कालेज की स्थापना होगी, जिससे आयुर्वेद उपचार एवं वैलनेस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा।

सुप्रभात

हो सके तो एक बार फिर से,
मिलना तुम मुझसे,
कोरे मन की समतल धरा पर,
खिलते ख्वाब की तरह।
जो पर्वतों से रिसकर सागर को ढूंढती हैं,
उन धाराओं की तरह नहीं,
समंदर की गहराइयों में छिपे,
बवंडर के सूक्ष्म राग की तरह।
वो साथ पक्षों में बंटें,
आधे-अधूरे चंद्रमा-सा ना हो,
संग मेरे रहना तुम,
सूरज के शाश्वत आकार की तरह।
क्षणभंगुर समय की टूटी कश्ती,
पर चढ़कर आना नहीं,
आना दूर तक फैले हरित मैदानों को,
लांघते घुड़सवार की तरह।
इस बार क्षितिज पर डूबती सांझ,
बनकर आना ना तुम,
तुम पहुंचना मुझतक,
आकाश के अनंत विस्तार की तरह।
जो पलकों का भार
बनकर अब भी टूट कर बिखरती है,
उन अश्रुओं की तरह नहीं,
ठहर जाना तुम, अधरों पर
मुस्कुराहटों के बौछार की तरह।
अब नहीं आना तुम, बंद दरवाजों में
गूंजती मेरी पुकार की तरह,
इस बार देना तुम दस्तकें,
खुलते आयामों के एक
नए संसार की तरह।

-मनीषा मंजरी

रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी पर विपक्ष ने लगाया दांव

उपराष्ट्रपति के लिए एनडीए के सीपी राधाकृष्णन से होगा मुकाबला

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंडिया ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। 79 साल के रेड्डी गुवाहाटी हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस और गोवा के पहले लोकायुक्त रह चुके हैं। वे आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। 2007 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। खास बात है कि दोनों उम्मीदवार दक्षिण से हैं। रिटायर जस्टिस रेड्डी आंध्रप्रदेश से, जबकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं। दोनों 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी। उसी दिन काउंटिंग भी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई की रात अचानक इस्तीफा देने की वजह से हो रहा है। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। सूत्रों का दावा है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के चुनाव में विपक्षी इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी की चली। ममता बनर्जी इस मुकाबले को तमिल वर्सेज तमिल बनाने को राजी नहीं थीं। साथ ही, उन्होंने प्रत्याशी के तौर पर नॉन पॉलिटिकल चेहरे रखने को कहा था। टीएमसी का कहना था कि अगर विपक्ष भी तमिल कैंडीडेट सामने लाएगा तो यह बीजेपी बनाम डीएमके हो जाएगा।

एनडीए की बैठक, उपराष्ट्रपति कैंडीडेट का सम्मान

मोदी बोले-राधाकृष्णन सरल और सहज व्यक्ति, वे राजनीति में खेल नहीं करेंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए। मोदी ने बैठक में महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी और सम्मानित किया। बैठक को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि राधाकृष्णन सरल और सहज व्यक्ति हैं। वे राजनीति में खेल नहीं करेंगे। इस दौरान राधाकृष्णन को एनडीए के सभी सहयोगी दलों के सांसदों से भी मिलवाया गया। बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि पीएम ने विपक्ष समेत सभी दलों से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद पर सर्वसम्मति से चुनने की अपील की है। 17 अगस्त को भाजपा संसदीय बोर्ड बैठक के बाद एनडीए की तरफ से राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया गया था। राधाकृष्णन 20 अगस्त को सुबह 11 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान 20 प्रस्तावकों और 20 समर्थकों समेत लगभग 160 सदस्यों के मौजूद रहने की उम्मीद है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 35 °c | न्यूनतम 30°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ बुधवार, 20 अगस्त 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

फौज के लिए सब कुछ झोंक दिया, दिव्यांग हुए तो कर दिया बाहर

500 जवानों को अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद! दायर की याचिका

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत में देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले युवाओं की कमी नहीं है। हजारों-लाखों नौजवान देश सेवा के लिए सेना में शामिल होने को तैयार रहते हैं। सेना में निकलने वाली भर्तियों के लिए कई गुना उम्मीदवार आवेदन करते हैं जिनमें से सिलेक्ट होने वाले टफ ट्रेनिंग के बाद सेना में शामिल होते हैं। जब देश के लिए अपना सब कुछ झोंक देने वाले जब ट्रेनिंग के दौरान चोटिल हो जाते हैं, यहां तक कि दिव्यांग भी हो जाते हैं उन्हें बाहर कर दिया जाता है। ऐसे ही 500 जवानों को इंसाफ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद से संज्ञान लिया है और केंद्र सरकार व तीनों सेनाओं से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को यह संज्ञान तब दर्ज किया जब एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि 1985 से अब तक देश के शीर्ष सैन्य संस्थानों में ट्रेनिंग के दौरान करीब 500 कैडेट्स घायल हुए या दिव्यांगता आई गई। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि जो कैडेट्स ट्रेनिंग के दौरान घायल या दिव्यांग हुए उन्हें मेडिकल के आधार पर बाहर कर दिया गया। उनमें से कई इलाज के लिए जूझ रहे हैं। हालांकि उन्हें मेडिकल ट्रीममेंट के लिए

40,000 रुपये महीना तक मुआवजा मिलता है, लेकिन यह बहुत कम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अकेले एनडीए में ही लगभग 20 ऐसे कैडेट हैं, जिन्हें 2021 से जुलाई 2025 के बीच केवल पांच वर्षों में चिकित्सा आधार पर सेवा से बाहर किया गया। 33 साल के शुभम गुप्ता उन नौजवानों में से हैं जो देश सेवा जज्बा लेकर सेना में भर्ती हुए लेकिन टफ ट्रेनिंग के दौरान ही अपना सब कुछ खो दिया। शुभम 2010 में लड़ाकू विमान उड़ाने का सपना लेकर एनडीए में शामिल हुए थे, लेकिन 2012 में एक डीप डाइव के दौरान रीढ़ की हड्डी में ऐसी चोट लगी कि आज वे अपने हाथ से पानी का गिलास तक नहीं उठा पाते। उनका गर्दन से नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया। उनकी 8 सर्जरी हो चुकी हैं और दो महीनों तक वेंटिलेटर पर भी रहे। सैनिक स्कूल के पूर्व छात्र रहे कार्तिक शर्मा साल 2015 से 2021 तक एनडीए का हिस्सा रहे थे। वे बचपन से ही एयरफोर्स में जाकर फाइटर पायलट सीट पर बैठना चाहते थे, लेकिन 27 साल के कार्तिक अब ऑटोमैटिक व्हीलचेयर पर बैठकर जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान लगी चोट की वजह से उनके लिंब्स कमजोर हो चुके हैं।

राजस्थान की मणिका विश्वकर्मा बनीं मिस यूनिवर्स इंडिया

देशभर की 47 मॉडल्स को पीछे छोड़ा, अब मिस यूनिवर्स के लिए भारत को करेंगी रिप्रजेंट

जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान के श्रीगंगानगर की रहने वाली मणिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया-2025 का खिताब जीता है। इस प्रतिष्ठित खिताब के लिए देशभर से जयपुर आईं 48

फाइनलिस्ट्स के बीच मुकाबला हुआ था। मणिका विश्वकर्मा अब 21 नवंबर 2025 को थाईलैंड के नोंथाबुरी स्थित इम्पैक्ट चैलेंजर हॉल में होने वाली मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। मणिका विश्वकर्मा ने कहा- मैं अपने देश को वर्ल्ड लेवल पर रिप्रजेंट करने को लेकर उत्साहित हूं। हमारे देश की संस्कृति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का मुझे मौका मिला है। यह मेरे लिए बहुत खास पल है। मणिका ने कहा- मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज अपने प्रदेश में मिलना भी सुखद है। मेरी कोशिश रहेगी कि समाज सेवा में भी मेरा योगदान हो। इसके लिए अभी से काम कर रही हूं।

संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं की जाएगी बर्दाश्त

असम सीएम बोले-राज्य में अजनबी लोग आ रहे, अगर सीमा पार की तो गिरफ्तार होंगे

गुवाहाटी (एजेंसी)। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दावा किया देश के कुछ हिस्सों से कुछ अजीबो-गरीब लोग असम आ रहे हैं, अगर वे सीमा पार करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मीडिया से बात करते हुए सरमा ने कहा कि ये लोग मुंबई और केरल के वकील थे। हम उन पर नजर रख रहे हैं। वे राज्य में एनआरसी अपडेट किए जाने के वक्त भी आए थे और उन्होंने पूरी प्रक्रिया को बिगाड़ दिया था। सरमा ने कहा- हम किसी भी

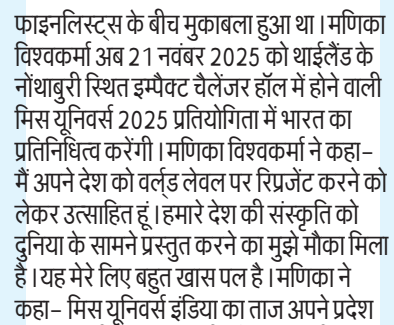

कट्टरपंथी गतिविधि या संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वे केरल से हों, मुंबई से या दिल्ली से। ये कट्टरपंथी हैं जो कुछ वर्गों की गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं और उनका संरक्षण करते हैं। सीएम सरमा ने कहा- एनआरसी प्रक्रिया के दौरान इन लोगों ने एक जैसे नामों का फायदा उठाया। उन लोगों के नाम दर्ज करके झूठे रिकॉर्ड बनाए गए जो लिस्ट में शामिल होने के योग्य नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि राज्य में पहले से रह रहे लोगों के झूठे रिश्तेदार बनाना सोशल वर्कर हर्ष मंदर जैसे कुछ व्यक्तियों के दिमाग की वजह से हुआ है। ये मुद्दे अब सामने आए हैं। पिछले 5 साल हमें ऐसी कई गड़बड़ियां मिली हैं, और अब हम इन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेश करने वाले हैं।

हवा साफ, फिर भी सड़कें जहरीली

भोपाल का एक्यूआई 36, फिर भी एक्सपर्ट दे रहे मास्क लगाने की सलाह

भोपाल (नप्र)। राजधानी की हवा इन दिनों रिकॉर्ड स्तर पर साफ है। कोहेफिजा में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 36, पर्यावरण परिसर में 51 और टीटी नगर में 38 दर्ज हुआ है। यानी राजधानी की हवा 'गुड' कैटेगरी में है। इसके बावजूद पर्यावरणविद् सुभाष सी. पांडे का कहना है कि शहर की कई सड़कें हार्ट के मरीजों और संवेदनशील लोगों के लिए जानलेवा बन चुकी हैं।

जिसकी वजह बारिश रुकने के बाद सड़कें उखड़ जाना और भारी वाहनों के गुजरने पर उठने वाला धूल का गुबार है।

बारिश के बाद सड़कें बनीं प्रदूषण का अड्डा- सुभाष सी पांडे बताते हैं कि आमतौर पर बरसात में हवा शुद्ध हो जाती है क्योंकि बारिश हानिकारक गैसों और प्रदूषकों को घोलकर जमीन पर गिरा देती है। मगर इस बार समस्या अलग है। पानी रुकने के बाद शहर की सड़कों की बजरी और डामर उखड़ गई है।

अब जब गाड़ियां गुजरती हैं तो धूल के कण हवा में फैलते हैं। इन कणों का साइज बड़ा होने से यह सीधे फेफड़ों और हृदय पर असर डालते हैं। यही वजह है कि एक्यूआई सामान्य होने के बावजूद धूलभरी सड़कों से स्वास्थ्य जोखिम कई गुना बढ़ गया है।

धूल और वाहनों का धुआं डबल डेंजर- उन्होंने कहा कि जब सड़क की धूल उड़ती है तो उसमें वाहनों से निकलने वाले धुएं का मिश्रण और घातक हो जाता है। इनमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन जैसी जहरीली गैस शामिल होती हैं। यह प्रदूषण सामान्य स्मोक से भी ज्यादा खतरनाक है और श्वसन रोग, आंखों की समस्याएं, त्वचा संबंधी बीमारियां और खासकर कार्डियोवस्कुलर डिसीज का खतरा बढ़ा देता है।

हार्ट पेशेंट्स और बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक

पांडे ने कहा कि 5 साल से छोटे बच्चे और 75 साल से अधिक उम्र के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। वहीं दिल के मरीजों के लिए इस समय धूलभरी सड़कों पर चलना जानलेवा साबित हो सकता है। उनके मुताबिक अगर लोग रोज इन्हीं रास्तों से गुजर रहे हैं तो मास्क लगाना बेहद जरूरी है। मास्क पहनने से करीब 70 प्रतिशत बीमारियों से बचाव संभव है।

इन सड़कों पर सबसे ज्यादा उड़ रही धूल

जहांगीराबाद
सुभाष नगर
जेल रोड
एमपी नगर
हबीबगंज
कमला पार्क
काजी कैंप
डीआईजी बंगला
हाउसिंग बोर्ड
भानपुर
शाहपुर
कॉलोनी
बैरागढ़ रोड
कोलार
तीन मोहरे
शाहजहानाबाद
जिंसी और ईदगाह।

भोपाल में 92 करोड़ की 61.2 किलो एमडी ड्रग्स जब्त

नशे की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़, डीआरआई ने चलाया ऑपरेशन 'क्रिस्टल ब्रेक'

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर नशे की अवैध फैक्ट्री पकड़ाई है। यहां से 92 करोड़ रुपए कीमत की 61.2 किलोग्राम मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग्स जब्त की गई है।

डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) ने ऑपरेशन 'क्रिस्टल ब्रेक' चला कर इस अवैध दवा निर्माण कारखाने का भंडाफोड़ किया है। अभियान के दौरान सूरत और मुंबई पुलिस ने भी डीआरआई की मदद की है। पीआईबी दिल्ली के अनुसार एक गोपनीय सूचना मिली थी। इसके बाद ही डीआरआई ने भोपाल में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। डीआरआई ने मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर छापे भी मारे और इस गिरोह के 7 प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया है।

जगदीशपुर इलाके में चल रही थी अवैध नशे की फैक्ट्री- बताया जा रहा है कि 16 अगस्त को भोपाल के जगदीशपुर (इस्लाम नगर) स्थित इस अवैध फैक्ट्री की तलाशी का अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में 61.2 किलोग्राम मेफेड्रोन लिक्विड रूप में बरामद कर जब्त की गई। जिसकी कीमत 92 करोड़ रुपए आंकी गई है।

इसके अलावा 541.53 किलोग्राम कच्चा माल, जिसमें मेथिलीन डाइक्लोराइड, एसीटोन, मोनोमेथिलमाइन (एमएमए), हाइड्रोक्लोरिक एसिड (एचसीएल) और 2 ब्रोमो शामिल हैं, उसे भी प्रोसेसिंग मशीनों के साथ जब्त किया है। मशीनों का पूरा सेट जांच में पाया है।

'लैंड जिहाद के माध्यम से बना देते हैं मस्जिदें-मजार'

भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग बोले- हठधर्मिता दिखाई तो सहन नहीं करेंगे

भोपाल (नप्र)। भोपाल में भदभदा डैम के पास स्थित मस्जिद को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सोमवार (18 अगस्त) को कहा कि भोपाल की सबसे बड़ी खूबसूरती इसके तालाब हैं। शहर को प्रकृति की ओर से मिला यह तोहफा किसी भी कीमत पर अतिक्रमण से बर्बाद नहीं होना चाहिए।

सारंग ने कहा कि लैंड जिहाद के माध्यम से मस्जिदें और मजार बना दी जाती हैं। तालाबों पर इस तरह के अतिक्रमण करना और मस्जिदों का दायरा लगातार बढ़ाना गलत है। आदेश के बाद निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। यदि इस तरह से हठधर्मिता दिखाई जाएगी तो यह सहन नहीं किया जाएगा।

पुराना विवाद, 100 साल पुरानी मस्जिदें- यह विवाद नया नहीं है। राजधानी की दिलकश मस्जिद और भदभदा डैम के पास की मस्जिद दोनों करीब 100 साल पुरानी बताई जाती हैं। ये वक्फ संपत्ति में पंजीकृत हैं। एडवोकेट रफी जुबेरी के अनुसार-इनका रिकॉर्ड 1937 से मौजूद है। दिलकश मस्जिद का गजट नोटिफिकेशन भी उपलब्ध है, जबकि भदभदा मस्जिद से सटा 1.44 एकड़ का कब्रिस्तान मस्जिद कमेटी के अधीन है।

नोटिस और कानूनी लड़ाई- 4 जुलाई को टीटी नगर तहसीलदार की ओर से मस्जिद कमेटी को नोटिस भेजा था, जिसमें कहा कि यह निर्माण अवैध है और इसे हटाया जाए। 7 जुलाई की सुनवाई के लिए तारीख तय की गई थी और साफ कर दिया था कि यदि मस्जिद कमेटी ने कार्रवाई नहीं की तो प्रशासन खुद हटाने की कार्रवाई करेगा। इस बीच वक्फ बोर्ड ने आपत्ति दर्ज कराई। बोर्ड का कहना है कि वक्फ संपत्ति पर बिना सुनवाई किसी भी तरह की कार्रवाई विधिसम्मत नहीं है।

ट्रेन सफर में ज्यादा सामान पर अब छह गुना जुर्माना

जनरल में 35 और एसी कोच में 70 किलो लिमिट

बैग-कार्टन के साइज पर भी चार्ज लगेगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को अब अपने लगेज (बैग और कार्टन) के वजन के साथ उसके साइज पर भी ध्यान देना होगा। अगर बैग हल्का है, लेकिन बड़े साइज और ज्यादा जगह घेरने वाला है तो टिकट के साथ आपको सामान की बुकिंग भी करानी होगी।

अगर आपने लगेज की प्री-बुकिंग नहीं कराई तो तय शुल्क से 6 गुना तक एक्स्ट्रा चार्ज और फाइन भी देना पड़ सकता है। भारतीय रेलवे ने देश के सभी जोन में एंट्री और एग्जिट गेट पर वजन करने वाली मशीनें लगाना शुरू कर दिया है। फिलहाल ये नया नियम कुछ बड़े स्टेशनों जैसे- कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, अलीगढ़, प्रयागराज जंक्शन और टुंडला स्टेशन पर लागू किया गया है। रेलवे धीरे-धीरे इसे पूरे देश के प्रमुख स्टेशनों पर लागू करने की तैयारी कर रहा है। भोपाल रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि कई यात्री ज्यादा सामान लेकर चलते हैं।

पंजाब में आतंकी संगठन बीकेआई की बड़ी साजिश नाकाम

- राजस्थान और कोलकाता से गिरफ्तार गुर्गों से मिला हैंड ग्रेनेड

जालंधर (एजेंसी)। पंजाब पुलिस की जालंधर काउंटर इंटेलीजेंस टीम ने बड़ी आतंकी साजिश नाकाम कर दी है। टीम ने बीकेआई (बब्बर खालसा इंटरनेशनल) से जुड़े गुर्गों से पूछताछ के बाद आतंकी वारदात में इस्तेमाल किया जाने वाला 86पी हैंड ग्रेनेड बरामद किया है। इससे पहले कुछ दिन पहले काउंटर इंटेलीजेंस ने राजस्थान निवासी आतंकी रितिक नरोलिया और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया था। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि रितिक और नाबालिग से पूछताछ के बाद मिली जानकारी पर कार्रवाई करते हुए उनके सहयोगियों को भी पकड़ा गया। इनमें विश्वजीत को कोलकाता से उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वह मलेशिया भागने की कोशिश कर रहा था, जबकि जैक्सन को नकोदर से दबोचा गया। इन्हीं गिरफ्तारियों के आधार पर हैंड ग्रेनेड बरामद किया जा सका और एक बड़ी आतंकी घटना होने से पहले ही रोक दी गई।

भारत को फर्टिलाइजर और रेयर-अर्थ मेटल देगा चीन

जुलाई में इनका निर्यात बैन किया था, दिल्ली पहुंचे चीनी विदेश मंत्री ने सहयोग का दिया भरोसा

नई दिल्ली (एजेंसी)। चीन भारत को खाद, रेयर अर्थ मटेरियल और टनल बोरिंग मशीन की सप्लाई करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री मंत्री वांग यी ने भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर को आश्वासन दिया कि इन जरूरतों को पूरा किया जाएगा। वांग यी 18 अगस्त को दो दिन के दौरे पर भारत

पहुंचे। उन्होंने सोमवार को जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बातचीत की थी। इस दौरान दोनों देशों ने आपसी रिश्तों को आगे बढ़ाने और सहयोग बनाए रखने पर सहमति जताई। चीन की सरकारी एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक वांग यी ने कहा- दुनिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं। फ्री ट्रेड और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत और चीन, जो सबसे बड़े विकासशील देश हैं और जिनकी आबादी मिलकर 2.8 अरब से ज्यादा है, उन्हें जिम्मेदारी दिखाते हुए एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिए।

राष्ट्रपति का कोर्ट से सलाह मांगना गलत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-हम अपनी राय बदल सकते हैं, फैसला नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आर्टिकल 143 के तहत कोर्ट से राय मांगना गलत नहीं है। मुर्मू ने मई में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी कि क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल विधेयकों पर फैसला लेने में अनिश्चितकाल तक देरी कर सकते हैं या कोई समयसीमा तय की जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई समेत 5 जजों की बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति सलाहकारी अधिकारिता में बैठी है, न कि अपील अधिकारिता में।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विश्व फोटोग्राफी दिवस की दी शुभकामनाएं

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्व फोटोग्राफी दिवस पर सभी फोटोग्राफरों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर प्रेस प्रकोष्ठ से जुड़े फोटोग्राफरों के साथ फोटो खिंचवाई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि फोटोग्राफी न केवल एक कला है, बल्कि यह जीवन के पलों को कैप्चर करने और उन्हें अमर बनाने का एक सर्व सुलभ साधन भी है। फोटोग्राफर हमारी सांस्कृतिक विविधता, प्रदेश की समृद्ध विरासत और सुंदरता को विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रभावी माध्यम हैं।

हमारे फोटोग्राफर साथी अपनी विधा में वैश्विक स्तर पर आ रही अद्यतन तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी रुचि और व्यवसाय में अग्रसर हों। साथ ही फोटोस के माध्यम से समाज को अविस्मरणीय पलों व भावों को सदा के लिए सहेजने की धरोहर सौंपते रहें।

सुदूर अंचलों तक हवाई पहुंच के लिए प्रदेश में किया जाएगा विमान सेवाओं का विस्तार

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सुदूर अंचलों तक हवाई पहुंच संभव करने के लिए सरकार द्वारा विमान सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य है, प्रदेश में हर 150 किलोमीटर पर एक हवाई अड्डा और हर 75 किलोमीटर पर एक हवाई पट्टी उपलब्ध हो। इससे न केवल शहरी क्षेत्र बल्कि ग्रामीण और दूरस्थ इलाके भी हवाई नेटवर्क से जुड़ सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने की कड़ी में रीवा, सतना और दतिया में नए हवाई अड्डों का शुभारंभ किया गया है। प्रदेश में हवाई अड्डों की संख्या बीते एक वर्ष में 5 से बढ़कर 8 हो गई है। शिवपुरी में नए हवाई अड्डे के लिए अनुबंध भी हो चुका है। मध्यप्रदेश हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल होने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से पर्यटन, व्यापार और आपातकालीन सेवाओं को बढ़ावा देना है। नए हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों के निर्माण से कनेक्टिविटी में सुधार होगा। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

बीड़ी और खनन श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई में सरकार देगी सहयोग

भोपाल(नप्र)। शैक्षणिक सत्र-2025-26 के लिए शिक्षा के लिये वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त शिक्षण-संस्थाओं में अध्ययनरत प्रदेश के बीड़ी, चूना पत्थर एवं डोलोमाट और लौह-मैग्रीज-क्रोम अयस्क खनन श्रमिक एवं उनके पुत्र-पुत्रियों को शिक्षा के लिये कक्षा एक से उच्च शिक्षा तक छात्रवृत्ति की राशि रूपये 1000/- से 25000/- स्वीकृत की गई है। योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिये पात्र विद्यार्थियों के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दिनांक-02.06.2025 से प्रारम्भ हो चुकी है। इसकी अंतिम तिथि प्री. मेट्रिक के लिये 31 अगस्त 2025 एवं पोस्ट मेट्रिक के लिये 31 अक्टूबर 2025 निर्धारित है। छात्रवृत्ति के लिये आवेदन करने के लिए ओ.टी.आर (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) और फेस ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। आवेदन की पात्रता व संबंधित अन्य जानकारी/शर्तें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करें जो कि स्पष्ट और पठनीय हो।

अस्थाई कनेक्शन लेकर ही झांकी-पंडाल की सज्जा करें : ऊर्जा मंत्री श्री तोमर

भोपाल (नप्र)। गणेशोत्सव त्यौहार तथा अन्य त्यौहारों में पंडालों को अस्थायी कनेक्शन देने के लिए विद्युत वितरण कंपनियों ने माकूल प्रबंध किए हैं। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे गणेशोत्सव के दौरान धार्मिक पण्डालों एवं झाँकियों में बिजली साज-सज्जा,नियमानुसार ऑनलाइन अस्थाई कनेक्शन लेकर ही करें।

मध्यप्रदेश अब बनेगा क्रिटिकल मिनरल्स हब : मुख्यमंत्री

मध्यप्रदेश में मिला रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार, चीन पर निर्भरता होगी समाप्त

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश अब क्रिटिकल मिनरल्स हब बनेगा। मध्यप्रदेश ऊर्जा राजधानी के साथ क्रिटिकल मिनरल्स की राजधानी भी कहलाएगा। इसके साथ ही भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी देश बनेगा। सिंगरौली जिले में रेयर अर्थ एलिमेंट्स (आरईई) का अकूत भंडार मिलने से अब भारत की चीन जैसे देशों पर निर्भरता नहीं रहेगी। केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने संसद में जानकारी दी थी कि भारत में पहली बार इतनी विशाल मात्रा में इन दुर्लभ तत्वों का पता चला है। यह उपलब्धि भारत को ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर बड़ा कदम- रेयर अर्थ एलिमेंट्स को आधुनिक तकनीक का आधार कहा जाता है। अब तक भारत इन खनिजों के लिए चीन और अन्य देशों पर निर्भर रहा है। प्रदेश के सिंगरौली की यह खोज भारत को आयात-निर्भरता से मुक्त कर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनाएगी। आने वाले समय में यह खोज आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देने के साथ ही औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देगी।

सिंगरौली-भविष्य का क्रिटिकल मिनरल हब- कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए शोध में सिंगरौली की कोयला खदानों और चट्टानों में आरईईएस (जैसे स्कैंडियम, यिट्रियम आदि) की आशाजनक सांद्रता पाई गई है।

कोयले में इनकी औसत मात्रा 250 पीपीएम और गैर-कोयला स्तर पर लगभग 400 पीपीएम आंकी गई है। जुलाई 2025 में इस खोज की आधिकारिक घोषणा हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में कोयले की राख और ओवरबर्डन भी क्रिटिकल मिनरल्स का सैकण्डरी स्रोत बन सकते हैं।

आईआरईएल के साथ सहयोग- रेयर अर्थ एलिमेंट्स की खोज को देखते हुए राज्य सरकार अब इनके प्रसंस्करण और शोध-अन्वेषण के लिए बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में जुटी है। हाल ही में खनिज संसाधन विभाग के प्रतिनिधिमंडल ने इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड (आईआरईएल) की भोपाल इकाई का दौरा किया और संभावित सहयोग पर चर्चा की।

विभाग रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की संभावनाएं तलाश रहा है, जो अनुसंधान, प्रशिक्षण और उद्योग को विश्वस्तरीय आधार प्रदान करेगा।

दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ दुग्ध-उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग जरूरी

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ दुग्ध उत्पादों की बेहतर ब्राडिंग, गोवंश की समुचित देखभाल, वेटनरी क्षेत्र में आवश्यक प्रशिक्षण और उन्नत अधोसंरचना स्थापित करने में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की विशेषज्ञता का हरसंभव लाभ लिया जाए। वर्ष 2030 तक प्रदेश के 26 हजार गांवों तक डेयरी नैटवर्क का विस्तार सुनिश्चित किया जाना है। इससे 52 लाख किलोग्राम दुग्ध संकलन होगा। बढ़े हुए दुग्ध संकलन का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आधुनिकतम दुग्ध प्रसंस्करण अवसंरचना विकसित की जाए। प्रदेश में निर्मित होने वाले दुग्ध उत्पादों की राष्ट्रीय स्तर पर ब्राडिंग सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और प्रदेश के दुग्ध संघों की गतिविधियों के संबंध में मंत्रालय में हुई बैठक को संबोधित कर रहे थे।

सभी विश्वविद्यालयों में वैटनरी के कोर्स किए जाएं संचालित-मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वैटनरी कॉउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में वैटनरी के कोर्स संचालित किए जाएं। उन्होंने नगरीय निकायों की बड़ी गो-शालाओं के उन्नयन और प्रबंधन में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से सहयोग लेने की आवश्यकता भी बताई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी दुग्ध संघों में एक समान उत्पाद निर्माण सुनिश्चित करने के लिए स्टेण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर अपनाना आवश्यक है। दुग्ध उत्पादकों को दुध-मूल्य के नियमित और समय पर भुगतान की व्यवस्था की नियमित मॉनीटरिंग हो। जिन क्षेत्रों में दुग्ध संघ की पहुंच सीमित है, वहां निजी दुग्ध व्यवसायियों को अद्यतन तकनीक का आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर दुग्ध व्यवसाय को प्रोत्साहित और सशक्त किया जाए। प्रदेश के दुग्ध संघ, मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और मध्यप्रदेश कृषि उद्योग निगम में बेहतर समन्वय सुनिश्चित हो।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की प्रदेश के दुग्ध संघों की गतिविधियों की समीक्षा

सभी दुग्ध संघ अपने सदस्यों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं नवाचार-बैठक में जानकारी दी गई कि सम्पूर्ण डेयरी चैन का डिजिटाइजेशन करने के लिए दुग्ध संघों में प्रक्रिया आरंभ की गई है। दुग्ध संकलन के लिए इंदौर दुग्ध संघ द्वारा मोबाइल एप का उपयोग आरंभ किया गया है, जिससे दुग्ध उत्पादकों को उनके द्वारा प्रदाय किए गए दूध की मात्रा, गुणवत्ता और मूल्य की जानकारी तत्काल प्राप्त होती है। भोपाल दुग्ध संघ द्वारा शहरी उपभोक्ताओं को दूध की गुणवत्ता की जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 'दूध का दूध-पानी का पानी' अभियान आरंभ किया गया है। भोपाल दुग्ध संघ ने 'सांची भात योजना' भी आरंभ की है, जिसमें सहकारी समितियों के सदस्यों की बेटियों के विवाह के अवसर पर दुग्ध संघ की ओर से 11 हजार रूपए और वस्त्र, भात के रूप में प्रदान किए जाएंगे। उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा पशुधन स्वास्थ्य में सुधार के लिए विशेष अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी विकास श्री उमाकांत उमराव, चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड डॉ. मीनेष शाह, वेटनरी कॉउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. उमेश शर्मा सहित पदाधिकारी उपस्थित थे।

नीट जी काउंसलिंग, पहले राउंड में कट-ऑफ कम

बीते साल था 621 ; पहले चरण में 4181 एमबीबीएस सीटें अलॉट

भोपाल (नप्र)। नीट यूजी स्टेट लेवल काउंसलिंग के पहले चरण में संचालनालय चिकित्सा शिक्षा (डीएमई) ने एमबीबीएस सीटों का आवंटन जारी कर दिया है। इस राउंड में कुल 4181 सीटें अलॉट हुईं। इन पर प्रवेश के लिए इस बार 15 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अधिकारियों के अनुसार, आवंटन पूरी तरह नियमों के अनुरूप किया गया।

इस साल काउंसलिंग में कुल 29 मेडिकल कॉलेज शामिल हुए। जिसमें 17 सरकारी और 12 निजी मेडिकल कॉलेज हैं। खास बात यह है कि पहले राउंड की कट-ऑफ पिछले वर्ष की तुलना में कम दर्ज की गई। सामान्य (आर) श्रेणी में 452, ओबीसी में 451 और ईडब्ल्यूएस में 496 नंबर पर आखिरी सीट अलॉट हुई। जबकि बीते साल सामान्य (आर) श्रेणी में यह 621 था।

एमबीबीएस की कुल 4775 सीटें

डीएमई से मिली जानकारी के अनुसार, एमबीबीएस की कुल 4775 सीटें हैं। इनमें से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में लगभग 2575 सीटों पर प्रवेश दिया जाना है, जिनमें से 2101 सीटें पहले चरण में स्टेट कोटा के तहत अलॉट कर दी गईं। निजी मेडिकल कॉलेजों में कुल 2200 सीटें हैं, जिनमें 1865 सीटें स्टेट कोटा में अलॉट हुईं, जबकि शेष सीटें एनआरआई कोटा के अंतर्गत आती हैं।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बची हुई सीटें विभिन्न आरक्षण व विशेष कोटा प्रावधानों के चलते रोकी गई हैं और अगले राउंड्स तथा अपग्रेडेशन में समायोजित होंगी।

भोपाल शीर्ष, इंदौर-ग्वालियर भी आकर्षण

पहले चरण में भोपाल अभ्यर्थियों की पहली पसंद रहा। यहां एक सरकारी कॉलेज के साथ पांच निजी मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। इसके अलावा एमजीएम मेडिकल कॉलेज,

इंदौर और ग्वालियर मेडिकल कॉलेज को भी बड़ी संख्या में छात्रों ने चुना।

19 से 23 अगस्त तक एडमिशन की विंडो

जिन अभ्यर्थियों को सीट अलॉट हुई है, उन्हें 19 से 23 अगस्त के बीच संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। इस दौरान फीस जमा करने के साथ मूल दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य है। तय समय सीमा में प्रक्रिया पूरी न करने पर सीट स्वतः रद्द मानी जा सकती है और वह अगले राउंड में चली जाएगी।

अच्छी रैंक लेकिन सीट नहीं

काउंसलिंग में कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी रहे जिनकी रैंक बेहतर होने के बावजूद उन्हें पहला विकल्प नहीं मिला या सीट अलॉट नहीं हुई। डीएमई अधिकारियों का कहना है कि कैटेगरी फिटमेंट, सीट मैट्रिक्स और विकल्पों की प्राथमिकता के चलते ऐसा हुआ है। ऐसे छात्र दूसरे राउंड में भाग ले सकते हैं और अपग्रेडेशन का विकल्प चुनकर बेहतर कॉलेज पाने की कोशिश कर सकते हैं।

आगे अभ्यर्थी क्या करें

कॉलेज रिपोर्टिंग- अलॉटमेंट लेटर, नीट स्कोरकार्ड, 10वीं-12वीं की मार्कशीट, डोमिसाइल, कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र, फोटो और अन्य दस्तावेजों के मूल व फोटोकॉपी साथ लेकर जाएं।

फीस व बॉन्ड- कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर और बॉन्ड और बैंक गारंटी (यदि लागू) को पहले से समझ लें, भुगतान के प्रमाण सुरक्षित रखें।

अपग्रेडेशन- जिनका वांछित कॉलेज नहीं मिला, वे अपग्रेडेशन चुनें। पर ध्यान रखें कि अपग्रेड होने पर पुरानी सीट खुद से छोड़ी मानी जा सकती है। नियम ध्यान से पढ़ें।

दस्तावेज सत्यापन- नाम, जन्मतिथि, कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी नॉन-क्रिमीलेयर की वैधता तिथि आदि में त्रुटि न रहे, वर्ना एडमिशन अटक सकता है।

एनआरआई कोटा- जो अभ्यर्थी एनआरआई कोटा पर विचार कर रहे हैं, वे पात्रता दस्तावेज (पासपोर्ट/स्पॉन्सर लेटर आदि) समय रहते तैयार रखें।

दूसरे राउंड में क्या बदलेगा

पहले राउंड की ज्वॉइनिंग के बाद वैकेंट सीटों की सूची जारी होगी। इसके आधार पर दूसरा राउंड और अपग्रेडेशन होगा। ज्वाइनिंग न करने, दस्तावेजों में कमी या फीस जमा न होने की स्थिति में खाली हुई सीटें अगले चरण में शामिल की जाएंगी। ईडब्ल्यूएस/ओबीसी/एससी-एसटी सहित आरक्षित श्रेणियों में कन्वर्जन नियम लागू होने से अंतिम राउंड्स में कट-ऑफ और सीट फ्लो में बदलाव संभव है।

कांग्रेस बोली- एमपी में 8-9 प्रतिशत वोट की चोरी हुई

सिंघार का आरोप- पिछले चुनाव में 16 लाख वोटर जोड़े, इसलिए हम 27 सीटों पर हारे

भोपाल (नप्र)। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। इसके बाद मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 2023 के विधानसभा चुनाव में करीब 16 लाख वोटों का हेरफेर किए जाने का आरोप लगाया है।

भोपाल में सिंघार ने कहा- हमने मध्य प्रदेश के बारे में चीजें समझी कि किस तरह से वोट चोरी कर फर्जी जनादेश लेकर भाजपा ने सरकार बनाई। इसमें चुनाव आयोग ने किस तरह से भाजपा की सरकारें बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई।

चुनावी साल 2023 में मध्य प्रदेश में 34 लाख से ज्यादा नाम जोड़े गए। अंतिम दो माह में हर रोज 26 हजार वोट जोड़े। टोटल 16 लाख वोट जोड़े गए। 2018 के चुनाव में भाजपा को कांग्रेस से 1 प्रतिशत से ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन 2023 में यह बढ़ कर 8-9 प्रतिशत हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में लगभग 8-9 प्रतिशत वोट की चोरी हुई।

ये मतदाता सूचियां देने में ही गड़बड़ है- नेता प्रतिपक्ष ने कहा- चुनाव आयोग कहता है कि हम पारदर्शिता रखते हैं। सभी पार्टियां हमारी स्टेकहोल्डर होती हैं। हर चुनाव में हम सभी राजनीतिक दलों को मतदाता सूची देते हैं। कौन सी सूचियां

देते हैं और कौन सी नहीं देते। कैसे वोट बढ़ाए या काटे जाते हैं। ये मतदाता सूचियां देने में ही गड़बड़ है।

सिंघार बोले- दो महीने में बढ़े थे 16 लाख वोटर- उमंग सिंघार ने मध्य प्रदेश में मतदाता सूची में गड़बड़ियों को उदाहरण समेत सामने रखा। सिंघार ने कहा- 2023 के विधानसभा चुनाव में दो महीने में ही करीब 16 लाख वोटर बढ़े थे। चुनाव आयोग ने एक पत्र 9 जून 2023 को छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मिजोरम और राजस्थान के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को जारी किया।

इसमें आदेश दिया कि मतदाता सूची में 30 जून के बाद जो वोटर हटाए, बढ़ाए गए वो लिस्ट चुनाव आयोग ने नहीं दी। आयोग ने साफ लिखा था कि ये लिस्ट न तो वेबसाइट पर डाली जाए और न ही किसी को दी जाए।

काम पर लौटे तहसीलदार-नायब तहसीलदार

13 दिन से काम बंद था ; भोपाल में 6 हजार केस पेंडिंग, सबसे पहले इन्हें निपटाएंगे

भोपाल (नप्र)। न्यायिक और गैर न्यायिक विभाजन से नाराज तहसीलदार और नायब तहसीलदार मंगलवार को काम पर लौट गए। वे पिछले 13 दिन यानी, 6 अगस्त से ही काम बंद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सोमवार को राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा एवं विभाग के सीनियर अधिकारियों से मुलाकात के बाद उन्होंने काम पर लौटने का निर्णय लिया।

मंगलवार को भोपाल में सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार काम पर लौट आए। हालांकि, उनके सामने 6 हजार से अधिक पेंडिंग मामलों को सबसे पहले निपटाने की चुनौती रहेगी। वे मप्र राजस्व अधिकारी (कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा) संघ के बैनरतले काम बंद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

भोपाल में जनता से जुड़े 500 मामले हर रोज आते हैं- जानकारी के अनुसार, नामांतरण, सीमांकन, फौती नामांतरण, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस सहित करीब 500 से अधिक मामले रोजाना आते हैं। इसके अलावा हर दिन करीब 300 प्रकरणों में तहसीलदार,नायब तहसीलदार सुनवाई करते हैं। इस वजह से दो दिन में ही 600 से ज्यादा केस की पेशियां आगे बढ़ा दी गई है। अब तक पेंडिंग केस का आंकड़ा 6 हजार तक पहुंच गया है।

फील्ड और ऑफिस के काम में विभाजित किए गए- भोपाल में बैरागढ़, कोलार, एमपी नगर, शहर वृत्त, बैरसिया और टीटी नगर तहसील हैं। इनके तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को न्यायिक और गैर न्यायिक कार्य में विभाजित किया है। यानी, जो अधिकारी न्यायिक कार्य कर रहे हैं, वे फिल्ड में नहीं है। वहीं, फील्ड वाले अधिकारी न्यायिक कार्य नहीं कर रहे।

इस व्यवस्था का वे भी विरोध कर रहे थे। इसके साथ ही कुल 8 मांगों को लेकर विरोध किया जा रहा था। इनमें से 7 मांगों पर सहमति बनने के बाद मंगलवार से तहसीलदार और नायब तहसीलदार काम पर लौट आए।

भोपाल में सरकारी बाबू एक लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

महिला कर्मचारी से जाति प्रमाण पत्र की जांच दबाने मांगे पांच लाख, जबलपुर लोकायुक्त ने पकड़ा

भोपाल (नप्र)। भोपाल में अनुसूचित जाति विकास कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड वन के बाबू को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने ये कार्रवाई की।

आरोपी बाबू जीवन लाल बरार ने छिंदवाड़ा में सहायक ग्रेड 2 में पदस्थ उषा दाभीरकर के जाति प्रमाण पत्र की जांच को दबाने के लिए 5 लाख रुपए मांगे थे। इसकी पहली किश्त लेकर आरोपी ने अपने घर जी-1 प्रशासनिक अकादमी के सामने पंचशील नगर भोपाल बुलाया था।

जाति प्रमाण पत्र की चल रही थी जांच- वाणिज्य कर कार्यालय छिंदवाड़ा में सहायक ग्रेड 2 में पदस्थ उषा दाभीरकर की जाति प्रमाण पत्र को लेकर कुछ समस्या थी। इसकी जांच कार्यालय आयुक्त अनुसूचित जाति विकास विभाग राजीव गांधी भवन भोपाल द्वारा की जा रही थी। उषा दाभीरकार की नौकरी 2 साल की बची थी। वरिष्ठ अधिकारियों से जांच दबाकर रखने के लिए आरोपी रिश्वत की डिमांड कर रहा था। जांच से बचने के लिए जीवन लाल बरार ने उषा से 5 लाख रुपए की डिमांड की। उसने यह भी आश्वासन दिया कि जांच पत्र अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाएगा।

नेमावर में एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से जल प्रदाय परियोजना का कार्य प्रगति पर

6,498 की आबादी को मिलेगा शुद्ध पेयजल

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधीनस्थ उपक्रम मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी द्वारा देवास जिले के नेमावर नगर परिषद् में एशियन डेवलपमेंट बैंक (ए.डी.बी.) के सहयोग से एक महत्वाकांक्षी जल प्रदाय परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। यह परियोजना 10 वर्षों के संचालन एवं संधारण के साथ लगभग 21 करोड़ रूपये की लागत से क्रियान्वित की जा रही है। इसके अंतर्गत 1640 घरों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे, जिससे 6,498 की आबादी को प्रतिदिन शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। परियोजना के तहत् मध्यप्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी से पानी लाकर उसे 2.41

एमएलडी क्षमता वाले जल शोधन संयंत्र में शोधित किया जाएगा। शोधित जल को लगभग 36 किलोमीटर लंबी वितरण पाइपलाइन के माध्यम से पूरे नगर में पहुँचाया जाएगा।

शहर में जल भंडारण के लिए 2 ओवरहैड टैंक का निर्माण भी पूर्णता की ओर है। इससे जल आपूर्ति व्यवस्था को स्थायित्व और नियमितता प्राप्त होगी। यह परियोजना नेमावर नगर में नागरिकों की मूलभूत आवश्यकता 'शुद्ध पेयजल'ह्य की सुनिश्चित आपूर्ति के लिये एक बड़ा कदम है। परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र के सामाजिक एवं स्वास्थ्य स्तर में भी उल्लेखनीय सुधार आयेगा।

संपादकीय

राधाकृष्णन के मुकाबिल रेड्डी

विपक्षी इंडिया गठबंधन द्वारा उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए बी. सुदर्शन रेड्डी के नाम की घोषणा किए जाने से यह साफ हो गया है कि देश के इस दूसरे सबसे बड़े पद का चुनाव आम सहमति से नहीं होगा। दूसरे, विपक्ष ने जिन पूर्व जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया है, वह तेलुगू हैं न कि तमिल। इसका अर्थ यह है कि इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक डीएमके की इस मांग को दरकिनार कर दिया गया है कि अगर भाजपा और एनडीए गठबंधन ने तमिल सी.पी. राधाकृष्णन को प्रत्याशी बनाया है तो विपक्ष भी किसी तमिल को ही मैदान में उतारे। ऐसे में डीएमके के सामने धर्मसंकट खड़ा हो सकता है। वह अंतिम समय में क्या निर्णय लेती है, ये देखना होगा। हालांकि ऐसा धर्म संकट तेलुगु देशम पार्टी के सामने भी हो सकता है, लेकिन चूंकि एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, इसलिए टीडीपी विरोध में जाएगी, इसकी संभावना बहुत कम है। बहरहाल रेड्डी के नाम की घोषणा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि हम सभी पार्टियों ने मिलकर एक कॉमन कैंडिडेट को उपराष्ट्रपति चुनाव में खड़ा करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि बी. सुदर्शन रेड्डी भारत के कुछ प्रगतिशील न्यायविदों में से एक हैं। खड़गे ने कहा, जब कभी भी संविधान और लोकतंत्र खतरे में होता है तो विपक्ष एक होकर अन्याय के खिलाफ़ लड़ता है। हम सब जानते हैं कि कैसे जस्टिस रेड्डी गरीबों के समर्थन में खड़े रहे और संविधान की सुरक्षा की। ये एक वैचारिक लड़ाई है। गौरतलब है कि 8 जुलाई 1946 को जन्मे बी. सुदर्शन रेड्डी ने 1971 में आंध्र प्रदेश बार काउंसिल के साथ वकालत शुरू की थी। 2 मई 1995 को वह आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के स्थायी जज नियुक्त हुए। साल 2005 में वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस बने। 2007 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया और साल 2011 में वह रिटायर हो गए। वे गोवा के पहले लोकायुक्त भी रह चुके हैं। उनका मुकाबला एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। दोनों 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी। उसी दिन काउंटिंग भी होगी। हालांकि चुनाव में वोटों के गणित के हिसाब से रेड्डी के जीतने की संभावना नहीं है। लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या 542 है। एक सीट खाली है। यहां एनडीए के 293 सांसद हैं। इसी तरह राज्यसभा में 245 सांसद हैं। 5 सीटें खाली हैं। यहां एनडीए के पास 129 सांसद हैं। माना जा रहा है कि राज्यसभा में नामांकित सदस्य भी एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे। इस तरह, सत्तारूढ़ गठबंधन को कुल 422 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। बहुमत के लिए 391 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। खास रणनीति के तहत कुछ पार्टियां गैर हाजिर भी रह सकती हैं। कुल मिलाकर बी. सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी विपक्ष का सांकेतिक विरोध ज्यादा है। अभी कहा जा रहा है कि चूंकि राधाकृष्णन घोर संघी पृष्ठभूमि से हैं, इसलिए उनका विरोध किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष ने तो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की उम्मीदवारी का भी विरोध किया था और मुकाबले में एक पूर्व भाजपा नेता यशवंत सिन्हा को खड़ा कर दिया था। जबकि धनखड़ संघी कतई नहीं थे। राधाकृष्णन और रेड्डी दोनों दक्षिण भारत से हैं। इसका अर्थ यह है कि भारतीय राजनीति के दोनों गठबंधन दक्षिण भारत को महत्व दे रहे हैं। फिर चाहे कोई हारे या जीते। उपराष्ट्रपति दक्षिण भारत से ही होगा। अगर सियासी दांव की दृष्टि से देखें तो भाजपा की चाल में संदेश छिपा है। राधाकृष्णन ओबीसी हैं तो रेड्डी अगड़ी जाति से हैं।

देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता

भारत का स्वतंत्रता संग्राम मात्र राजनीतिक मुक्ति की लड़ाई नहीं थी, यह आत्म-स्मृति की पुनःस्थापना का एक ऐसा संकल्प था, जो शोषण के विरुद्ध जनगण के अंतर्मन से उठी पुकार बन गया। यह वही संघर्ष था, जो महात्मा गांधी की करुणा, भगत सिंह की चेतना, सुभाष बोस की गर्जना और सावरकर की निर्भीकता में एकसाथ जीवंत हो उठा। हर स्वतंत्रता दिवस पर जब लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया जाता है, तो इतिहास बताता है कि यह वही दीवार है, जिसने औरंगज़ेब की हिंसा देखी, बहादुरशाह ज़फ़र की विवशता झेली और 1857 की क्रांति के नायकों का लहू बहते देखा। यह कोई निष्प्राण दीवार नहीं, यह भारतीय सामाजिक चेतना की प्रतीक है।

नजरिया

डॉ. खुशालसिंह पुरोहित
लेखक पत्रकार हैं।

भारत केवल 1947 में जन्मा नवीन राष्ट्र नहीं, अपितु सप्तसिन्धु की गोद में पला, वेदों के स्वर में गूंजता, उपनिषदों की चिंतनधारा में बहता, एक प्राचीन राष्ट्र है, जिसकी सांस्कृतिक चेतना हजारों वर्षों से अक्षुण्ण रही है। भारतवर्ष की पहचान सनातन सांस्कृतिक मूल्यों से है। हम भारत माता की जय बोलते हैं जो धर्म, दर्शन, साहित्य, संगीत, कला और जनमानस की राष्ट्रीय चेतना की प्रतीक हैं। यह जयघोष बताता है कि भारत हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और द्वारका से लेकर कामरूप तक भाषा, बोली और सामाजिक परंपराओं में विविधता होते हुए भी विचारों में एक है।

भारत का स्वतंत्रता संग्राम मात्र राजनीतिक मुक्ति की लड़ाई नहीं थी, यह आत्म-स्मृति की पुनःस्थापना का एक ऐसा संकल्प था, जो शोषण के विरुद्ध जनगण के अंतर्मन से उठी पुकार बन गया। यह वही संघर्ष था, जो महात्मा गांधी की करुणा, भगत सिंह की चेतना, सुभाष बोस की गर्जना और सावरकर की निर्भीकता में एकसाथ जीवंत हो उठा। हर स्वतंत्रता दिवस पर जब लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया जाता है, तो इतिहास बताता है कि यह वही दीवार है, जिसने औरंगज़ेब की हिंसा देखी, बहादुरशाह ज़फ़र की विवशता झेली और 1857 की क्रांति के नायकों का लहू बहते देखा। यह कोई निष्प्राण दीवार नहीं, यह भारतीय सामाजिक चेतना की प्रतीक है।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम असंख्य बलिदानों की महागाथा है। भगतसिंह, राजगुरु, सुखदेव का हँसते हुए बलिदान, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफ़ाकउल्ला और रामप्रसाद बिस्मिल की राष्ट्रवादी निष्ठा, गांधीजी के सत्याग्रह, नेताजी सुभाषचंद्र बोस की आज़ाद हिंद फ़ौज, सरदार पटेल, डॉ राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं की प्रखर राजनीति और जनआंदोलनों के आगे ब्रिटिश साम्राज्य टिक नहीं सका।

आज जब हम स्वतंत्र हैं, तो यह स्वतंत्रता ऋण है, उन अनगिनत ज्ञात और अज्ञात बलिदानियों का जिनकी चिंताओं में भारत का भविष्य बसता था। परंतु क्या हमने इन स्वतंत्रता सेनानियों के मर्म को सही अर्थों में समझा है? क्या हमने अपनी सांस्कृतिक आत्मा को पुनः पहचाना है? आज का भारत वैश्विक मंच पर आगे बढ़ रहा है, परंतु उसकी वास्तविक प्रगति तभी सार्थक होगी जब वह अपने सनातन जीवनमूल्यों, भाषाओं और सामाजिक परंपराओं के साथ आगे बढ़ेगा।

हमें ऐसे भारत का निर्माण करना है जो विज्ञान में अग्रणी हो और आध्यात्म की दृष्टि से भी जाग्रत; जो तकनीकी ज्ञान से समृद्ध हो पर संस्कारों से भी अनुप्राणित हो। आज का युवा उत्तराधिकारी बने भारतीय मनीषा की उस परंपरा का जो वाल्मीकि से विवेकानंद तक, कृष्ण से चाणक्य तक, पतंजलि से भास्कराचार्य तक और आर्यभट्ट से योगीराज अरविंद तक फैली हुई है।

प्रधानमंत्री ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं, तो ये भाषण समकालीन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब होते हैं। इन संदेशों की सामाजिक प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर रही है कि किस प्रधानमंत्री ने किस मुद्दे को किस दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया और वह जन सरोकारों से कितना जुड़ पाया। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए गए अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों के संदेश केवल भाषण नहीं रहे, बल्कि वे भारतीय समाज में विचारों, मूल्यों और व्यवहार में परिवर्तन लाने में अग्रणी रहे हैं। हर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में उस कालखंड की सामाजिक आवश्यकताओं और चुनौतियों की चर्चा की है।

पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता दिवस के भाषणों में राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, औद्योगिकीकरण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने पर जोर देते थे। उनके भाषणों से समाज में आधुनिक सोच, सामाजिक सुधार और लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई। लाल बहादुर शास्त्री ने 'जय जवान - जय किसान' का नारा लाल किले से दिया, जिसने समाज को सैनिकों और किसानों के सम्मान के लिए प्रेरित किया।

इंदिरा गांधी के भाषणों में 'गरीबी हटाओ' जैसे नारों ने समाज के निचले तबकों में भविष्य की नयी उम्मीद जगाई। 1971 के 'बांग्लादेश मुक्ति संग्राम' के बाद लाल किले से अनके भाषण ने समाज में राष्ट्रीय गौरव का भाव भरा था, परन्तु लोकतांत्रिक मूल्यों के दमन के प्रतीक 1975 के आपातकाल से उनकी छवि और सामाजिक विश्वसनीयता प्रभावित हुई, नतीजतन 1977 के चुनावों में उन्हें भारी पराजय का सामना करना पड़ा। मोरारजी देसाई के भाषणों में लोकतंत्र की बहाली की झलक और नागरिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता पर जोर देने से नागरिकों में लोकतंत्र के प्रति भरोसा पुनः जाग्रत हुआ था।

राजीव गांधी ने युवा भारत और टेक्नोलॉजी आधारित विकास की बात कही थी। कंप्यूटर, संचारक्रांति और पंचायती राज की बातें उनके भाषणों के केंद्र में रहती थीं, जिससे समाज में डिजिटल परिवर्तन तथा युवा और महिला सशक्तिकरण की शुरुआत हुई। वीपी सिंह के लाल किले के भाषण से समाज में सामाजिक न्याय और आरक्षण की नयी बहस आरम्भ हुई जिसने देश को हिंसक आंदोलन में झोंक दिया। नरसिम्हा राव के भाषणों में आत्मनिर्भरता, आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा रहती थी। इसी दौर में समाज में रोजगार, निजी क्षेत्र की भागीदारी और उपभोक्तावाद की नई संस्कृति का आरंभ हुआ।

अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण भावनात्मक, प्रेरक और राष्ट्रवाद की भावना वाले होते थे। उनके भाषण सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से यथार्थ की यात्रा के भी परिचायक हैं। अटल जी द्वारा कही गयी 'भारत उगता हुआ सूरज है' जैसी पंक्तियों ने युवाओं और आम जनता में गर्व की भावना भरी। 'पोखरण परमाणु परीक्षण' और 'कारगिल विजय' के बाद उनके भाषणों ने देशभक्ति की भावना को मजबूत किया। डॉ. मनमोहन सिंह के भाषण में सामाजिक समावेश, शिक्षा, सूचना का अधिकार और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की चर्चा रहती थी। उनके भाषण में आमतौर पर आर्थिक दृष्टि से भारत में स्थायित्व और सुधारों पर जोर रहता था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों से लाल किले को एक जन-संवाद मंच में बदलने का प्रयास किया है। 'स्वच्छ भारत अभियान', 'जन धन योजना', 'हर घर जल' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी योजनाओं की शुरुआत की है। मोदी के कुछ भाषणों ने नागरिकों की मानसिकता में व्यावहारिक बदलाव कर उनके विचारों को जनआन्दोलन बना दिया।

भारत में जब तक अंतिम नागरिक के जीवन में गरिमा, समानता, और संप्रभुता का प्रकाश नहीं पहुंचेगा, तब तक स्वतंत्रता का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। आज जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो यह आत्मावलोकन करने का अवसर है कि क्या हम आज भी आत्मनिर्भर हैं? क्या हमारी नीतियाँ अपनी मिट्टी और देशज परंपराओं से उपजी हैं? आज हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ भारत पर बहुआयामी संकट के बादल घने होते जा रहे हैं। आज हर मोर्चे पर मौजूद संकट में सांस्कृतिक अतिक्रमण, वैचारिक विखंडन और तकनीकी उपनिवेशवाद प्रमुख है।

देश में ज्यादातर लोग अपनी भाषाओं को और अपनी परम्पराओं को पिछड़ापन समझने लगे हैं। समाज में वैचारिक विखंडन और सामाजिक ध्रुवीकरण आज मीडिया, सोशल मीडिया और शिक्षण संस्थानों तक पहुँच रहा है। युवा पीढ़ी इतिहास से विमुख हो रही है, उन्हें भारत की परंपरा, दर्शन और संघर्षों से अनभिज्ञ रखा जा रहा है। आज के संकटों से लड़ने के लिए भारत में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान की आवश्यकता है। आज हमें आत्ममंथन करना होगा, इस दिन उस चेतना को जगाना होगा जो एक संस्कारशील राष्ट्र बनाती है। (सप्रेस)

देश विभाजन के दोषी कौन?

विचार

प्रमोद भार्गव
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

भारत में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर जारी एक विशेष पाठ में भारत के बंटवारे के लिए मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस और तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लार्ड माउंटबेटन को जिम्मेदार ठहराया है। पाठ में यह भी उल्लेख है कि विभाजन के बाद कश्मीर नई समस्या के रूप में पेश आया। भारत में यह समस्या पहले कभी मौजूद नहीं थी। इसने देश की विदेश नीति के लिए चुनौती बनाए रखी। नतीजतन कुछ देश पाकिस्तान को सहायता देते रहते हैं और कश्मीर मुद्दे के नाम पर भारत पर दबाव बनाते रहते हैं। वस्तुतः 'भारत का विभाजन गलत विचारों के कारण हुआ। भारतीय मुसलमानों की पार्टी मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर में एक सम्मेलन आयोजित किया। इसमें जिन्ना ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग धार्मिक दर्शन, सामाजिक रीति-रिवाज से संबंधित हैं। अतएव एक साथ नहीं रह सकते।' एनसीईआरटी के विशेष पाठ में 'विभाजन के अपराधी' शीर्षक वाले खंड में कहा है कि 'अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा हुआ। किंतु यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था। इसके लिए तीन कारण जिम्मेदार थे, एक जिन्ना, जिन्होंने बंटवारे की मांग की। दूसरे कांग्रेस, जिसने बंटवारे को स्वीकार किया और तीसरे माउंटबेटन जिन्होंने इस पर अमल किया। माउंटबेटन एक बड़ी भूल के दोषी साबित हुए।'

एनसीईआरटी ने उक्त दो पार्ट छापे हैं। इनमें छठी कक्षा से आठवीं के लिए और नौवीं कक्षा से बारहवीं के लिए एक-एक पाठ हैं। ये अंग्रेजी और हिंदी में पूरक पाठ हैं, नियमित पाठ्य पुस्तकों में नहीं हैं। इसलिए इनका प्रयोग परियोजनाओं, पोस्टरों और वाद-विवादों के माध्यम से किया जाना है। ये दोनों पाठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में दिए गए संदेश के साथ शुरू होते हैं, जिसमें विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। साफ है, ये पाठ पूरे देश में वाद-विवाद का ऐसा हिस्सा बनें, जिससे लोग जान सकें कि वास्तव में विभाजन के अपराधी कौन हैं। केंद्र सरकार इस उद्देश्य की पूर्ति में सफल होती दिख रही है। दरअसल स्वतंत्रता संघर्ष के बीच महात्मा गांधी ने आत्मविश्वास से कहा था कि 'अगर कांग्रेस बंटवारे को स्वीकार करना चाहती है तो उसे मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। जब तक मैं जीता हूं, मैं कभी भी हिन्दुस्तान का बंटवारा स्वीकार नहीं करूंगा और जहां तक मेरा वश चलेगा कांग्रेस को भी स्वीकार नहीं करने दूंगा।' अलबत्ता ऐसा एकाएक क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को बंटवारे के समर्थन में खड़े होना पड़ गया। लार्ड माउंटबेटन से पहली मुलाकात में ही गांधी उनके वाग्जाल की गिरफ्त में ऐसे आए कि उनकी प्राण जाए, पर वचन न जाए, की वचनबद्धता भंग हो गई। कांग्रेस मुस्लिम अलगाववाद के आगे घुटने टेकती चली गई। नतीजतन भारत और पाकिस्तान स्वतंत्रता अधिनियम पर ब्रिटिश संसद में मोहर लगा दी गई। ब्रितानी हुकूमत में औपनिवेशिक दासता झेल रहे अखंड भारत को विभाजित कर दो स्वतंत्र देश बनाकर पृथक-पृथक सत्ता का हस्तांतरण करने का निर्णय ले लिया। संपूर्ण सत्ता सौंपने का दिन 14 अगस्त 1947 निश्चित किया। यह दिन भी एक तरह से दोनों देशों के स्वतंत्रता सेनानियों को चिढ़ाने की दृष्टि से मुकर्रर किया गया, क्योंकि इसी दिनांक को जापान मित्र देशों के समक्ष आत्मसमर्पण करने को मजबूर हुआ था।

अंग्रेजों द्वारा अपनी सत्ता कायम रखने की दृष्टि से बंगाल विभाजन एक ऐसा षड्यंत्रकारी घटनाक्रम रहा जो भारत विभाजन की नींव डाल गया। इस बंटवारे के फलस्वरूप अंग्रेजों के विरुद्ध ऐसी उग्र जनभावना फूटी की बंग-भंग विरोध में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। दरअसल जब गोरी पलटन ने समूचे भारत को अपनी अधीनता में ले लिया, तब क्रांतिकारी संगठनों और विद्रोहियों के साथ कठोरता बरतने के लिए 30 सितंबर 1898 को भारत की धरती पर वाइसराय लॉर्ड कर्जन के पैर पड़े। कर्जन को 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरणा ले रहे क्रांतिकारियों के दमन के लिए भेजा गया था। इस संग्राम पर नियंत्रण के बाद फिरंगी इस बात को लेकर चिंतित व सर्तक थे, कि कहीं इसकी राख में दबी चिंगारी फिर न सुलग पड़े। क्योंकि अंग्रेज भली भांति जान गए थे कि 1857 का सिलसिला टूटा नहीं है। अंग्रेजों को यह भी शंका थी कि कांग्रेस इस असंतोष को पनपने के लिए खाद-पानी देने का काम कर रही है। कर्जन ने अंग्रेजी सत्ता के संरक्षक बने मुखबिरों से ज्ञात कर लिया कि इस असंतोष को सुलगाए रखने का काम बंगाल से हो रहा है। वाकई स्वतंत्रता की यह चेतना बंगाल के जनमानस में एक बेचैनी बनकर तैर रही थी। यह बेचैनी 1857 के संग्राम जैसे रूप में फूटे, इससे पहले कर्जन ने कुटिल क्रूरता के साथ 1905 में बंगाल के दो टुकड़े कर दिए। जबकि इस बंग-भंग का विरोध हिंदू और मुसलमानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर किया था। इस बंटवारे का मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पूर्वी बंगाल और हिंदू बहुल इलाके को बंगाल कहा गया। अर्थात् जिस भूखंड पर हिंदू-मुस्लिम संयुक्त भारतीय नागरिक के रूप में रहते चले आ रहे थे, उनका मानसिक रूप से सांप्रदायिक विभाजन कर दिया। इस विभाजन से सांप्रदायिक भावना की एक तरह से बुनियाद डाल दी गई, वहीं दूसरा इसका सकारात्मक परिणाम यह निकला कि पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष तेज हो गया। यानी फिरंगी-सत्ता के विरुद्ध एकजुटता ने देशव्यापी उग्र भावना का संचार अनजाने में कर दिया। लेकिन कर्जन ने इसे कुटिल चतुराई से मुस्लिम लीग की स्थापना में बदल दिया।

6 दिसंबर 1946 ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक तीन सदस्यीय शिष्टमंडल भेजा। ये लार्ड लारेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। इन्हें शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए भेजा गया था। इस मिशन ने कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधियों से बातचीत की और सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए हिंदू-मुस्लिमों के बीच साझा सत्ता की योजना को मूर्त रूप देना चाहा। इस संवाद में अनेक विरोधाभासी पहलू सामने आए। जिन्ना भारत के साथ रहना तो चाहते थे, लेकिन संविधान में मुसलमानों को विशेष राजनीतिक संरक्षण गारंटी चाहते थे। जिसमें हिंदूओं के साथ बराबरी की मांग प्रमुख थी। यही वह दौर था, जिसमें ठीक दीपावली पर्व के बीच नोआखली में भयंकर सांप्रदायिक दंगे भड़के। मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू नरसंहार, मंदिरों का विध्वंस और आगजनी की दर्जनों घटनाएं घटी। हिंदू महिलाओं का अपहरण, दुष्कर्म और धर्मांतरण कराकर जबरन विवाह भी रचाए गए। इन घटनाओं से गांधी को जबरदस्त सदमा पहुंचा और शांति के लिए नोआखली पहुंच गए। बहरहाल कैबिनेट मिशन की शिमला बैठक में कोई कारगर परिणाम नहीं निकला।

लॉर्ड माउंटबेटन इतना चतुर निकला कि उसने विभाजन के लिए जिन्ना, नेहरू, पटेल और यहां तक की गांधी को भी मना लिया। भारत को दो स्वतंत्र राष्ट्रों में भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया। यही नहीं पंजाब और बंगाल को भी कपड़े की तरह दो टुकड़ों में चीर दिया गया,जिससे भारत हमेशा गृह कलह की आंच से सुलगता रहे। यह पाकिस्तान के अस्तित्व से भी ज्यादा खतरनाक था। ब्रिटिश अधिकारियों ने जानबूझ कर 652 भारतीय रियासतों की प्रभुसत्ता उन्हें वापस सौंप दी। उन्हें भारत या पाकिस्तान मिल जाने की छूट तो थी ही, स्वतंत्र राष्ट्र बने रहने की छूट भी दे दी गई थी। अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ विभाजन तो आधा सच है, पूरा सच तो देश के 652 टुकड़े कर देने का बन गया था। जिसे पटेल ने संभाला और रियसतों का विलय भारतीय गणतंत्र में हो पाया। अतएव जिन दो पाठों में जिन्ना, कांग्रेस और लाउंटबेटन को दोषी ठहराया गया है, वह कोई केंद्र की वर्तमान सरकार का झूठ नहीं, अपितु ऐतिहासिक सत्य है, जो निष्पक्ष भाव से लिखे स्वतंत्रता आंदोलन की इतिहास पुस्तकों में पूर्व से ही दर्ज है।

क्या भविष्य में फोटोग्राफर बेरोजगार हो जाएंगे?

विश्व फोटोग्राफी दिवस

अबरार खान
लेखक फोटो जर्नलिस्ट हैं।

पल पल बदलती तकनीक के दौर में हम विश्व फोटोग्राफी दिवस मना रहे हैं, तो यह सवाल स्वाभाविक है कि तकनीक के इस दौर में फोटोग्राफरों का भविष्य कैसा होगा? स्मार्टफोन कैमरे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडिटिंग टूल्स ने फोटोग्राफी को बेहद आसान बना दिया है। अब हर हाथ में कैमरा है और हर कोई खुद को फोटोग्राफर कहने लगा है।

लेकिन असली फोटोग्राफी सिर्फ क्लिक करना नहीं है। एक पेशेवर फोटोग्राफर रोशनी, एंगल, भावनाओं और सही क्षण को कैद करने की कला जानता है। यही कला उन्हें आम भीड़ से अलग करती है। तकनीक चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन इंसानी संवेदनाओं को महसूस करके उन्हें तस्वीर में ढालना केवल एक संवेदनशील कलाकार ही कर सकता है।

भविष्य में फोटोग्राफरों की भूमिका बदल जरूर सकती है, लेकिन खत्म नहीं होगी। वे डॉक्यूमेंट्री, फैशन, वेडिंग, नेचर और आर्टिस्टिक फोटोग्राफी में और भी नए अवसर पाएंगे। साथ ही एआई और डिजिटल टूल्स का सही उपयोग करने वाले फोटोग्राफर और भी ज़्यादा डिमांड में रहेंगे। इसलिए कहा जा सकता है कि फोटोग्राफर कभी बेरोज़गार नहीं होंगे, बल्कि बदलते समय के साथ उनकी कला और भी निखर कर सामने आएगी।

फोटो जर्नलिज़्म कभी अख़बारों की पहचान सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि उन तस्वीरों से भी होती थी जो सीधे पाठकों के दिल को छू जाती थीं। एक असरदार फोटो, पूरी खबर से कहीं ज्यादा बोल जाती थी। यही वजह थी कि फोटो जर्नलिज़्म को अख़बारों की आत्मा कहा जाता था। लेकिन अफसोस, आज यह आत्मा धीरे-धीरे ग़ायब होती जा रही है।

डिजिटल मीडिया और सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स ने तस्वीरों की बाढ़ ला दी है। अब हर मोबाइल कैमरा एक तरह से 'रिपोर्टर' बन गया है। न्यूज़ एजेंसियों और इंटरनेट से मिलने वाली तैयार तस्वीरों ने अख़बारों में समर्पित फोटो पत्रकारों की ज़रूरत को कम कर दिया है। नतीजतन, पेशेवर फोटो जर्नलिज़्म अपनी अहमियत खोता जा रहा है।

लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई भी तस्वीर सच को उतनी गहराई से बयां कर सकती है, जितनी एक फोटो जर्नलिस्ट की संवेदनशील नज़र इतिहास गवाह है-युद्धों से लेकर स्वतंत्रता आंदोलनों तक, आपदाओं से लेकर आम जनजीवन तक-सबसे विश्वसनीय गवाही हमेशा तस्वीरें ही रही हैं। ये तस्वीरें केवल दृश्य नहीं, बल्कि समय की दस्तावेज़ और समाज की आवाज़ होती हैं।

विश्व फोटोग्राफी दिवस पर यही सोचने की जरूरत है कि अगर अख़बारों से फोटो जर्नलिज़्म मिटता गया, तो आने वाली पीढ़ियों के पास सिर्फ शब्द रह जाएंगे, लेकिन घटनाओं की आत्मा नहीं। सच तो यही है–बिना तस्वीर, खबर अधूरी है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्र निर्माण की एक हास्यगाथा

व्यंग्य

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उरतृप्त
लेखक व्यंग्यकार हैं।

अगर कोई पूछे कि लोकतंत्र क्या है, तो संविधान की मोटी किताब मत खोलिए–बस इस बस स्टॉप पर एक घंटे खड़े हो जाइए। लोकतंत्र वहाँ है जहाँ जनता धूल फाँक रही होती है और अफसर फाइलों में 'प्रगति' के नक्शे रंग रहा होता है। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ आदमी सिर पर जूट का थैला लिए खड़ा रहता है, जैसे वह अपने ही जीवन का कुल जमा सामान ढो रहा हो। एक औरत जो अपने बच्चे को गोद में लेकर खड़ी है, उसकी निगाहें बस की राह नहीं, बल्कि उस वादे की राह देख रही हैं जो हर चुनाव में दोहराया गया–'बेहतर सार्वजनिक परिवहन मिलेगा।' उधर ठेकेदार अपने कर्मचारियों को चाय पिलाता है और कहता है, 'काम कल से शुरू करेंगे,' और 'कल' कभी नहीं आता। मंत्रीजी जब उद्घाटन के लिए आते हैं तो उनके पीछे दस कैमरे होते हैं और पंद्रह चमचे, और सामने सिर्फ एक बेंच होती है, जो उद्घाटन से पहले ही टूट चुकी होती है। 'योजना सफल रही,' यह घोषणा तब होती है जब बोर्ड टंग चुका होता है और धरातल पर कुछ नहीं बदला होता। सबसे मज़ेदार तो यह है कि फाइलों में यह बस स्टॉप अब 'मॉडल बस टर्मिनल' बन चुका है, जिसमें वाई-फाई से लेकर महिला विश्राम कक्ष तक की सुविधा दर्शाई गई है–पर असलियत में वहां सिर्फ दो गड्ढे, तीन झोपड़ीनुमा दुकानें और एक बोरिंग का पाइप दिखता है, जिससे कभी-कभी पानी नहीं, सिर्फ हिचकियाँ आती हैं। यह प्रतीक्षा कक्ष नहीं, लोकतंत्र का पोस्टर है–जिसे हम सब निहारते हैं, जीते हैं, और हर बार जब सरकार नया स्लोगन लांच करती है, तो हम उसे फोल्ड करके जेब में रख लेते हैं–इस उम्मीद के साथ कि अगली बार शायद वाकई कुछ बदलेगा। लेकिन यहाँ तो धूल तक को सरकारी पहचान मिल चुकी है–'सांस्कृतिक धरोहर' के नाम पर।

बस स्टॉप पर प्रतीक्षा केवल बस की नहीं होती–वो प्रतीक्षा होती है अच्छे दिनों की, सुविधाओं की, और उस इंसानियत की जो सरकारी घोषणाओं में तो दिखती है, पर ज़मीन पर गायब रहती है। जैसे ही कोई नेता 'जनता की सेवा में' कहकर माइक थामता है, उसी समय एक गरीब बच्चा माँ का पल्लू पकड़कर कहता है, 'माँ, आज भी स्कूल की बस नहीं आई।' माँ कुछ नहीं कहती–क्योंकि उसे पता है कि स्कूल की बस से ज़्यादा ज़रूरी है घर की रसोई। उधर घोषणाओं की लिस्ट में अब 'ग्रीन एनर्जी से चलने वाली बसें' भी शामिल हैं, लेकिन जनता अब भी पैदल चलती है–क्योंकि सड़कों पर बसें कम, गड्ढे ज़्यादा हैं। हर साल एक नया टेंडर पास होता है, और हर साल वही पुराना ठेकेदार कम दाम में अधूरा काम करता है–क्योंकि 'कमीशन' लोकतंत्र की वो गूंगी जुबान है, जो हर निर्माण में बोलती है।

अफसर की गाड़ी धूल उड़ाते हुए निकलती है, और जनता मुंह ढँककर खुद को समझाती है–'कम से कम गाड़ी आई तो सही!' ये आशावादिता नहीं, बल्कि अभाव में जीने की आदत है। किसी कवि ने कहा था, 'हम इंतज़ार में भी जिए, और उसी में मर गए।' और ये बस स्टॉप उसी भावना का जीवित चित्र है–जहाँ जनता खड़ी है, नारे हवा में हैं, योजनाएँ कागज़ पर हैं, और वक्त धूल के कणों में उलझा पड़ा है।

अभी हाल में सरकार ने घोषणा की कि इस बस स्टॉप पर 'स्मार्ट शेल्टर' बनेगा–माने ऐसा शेल्टर जो दिखे नहीं, लेकिन उसकी योजना की फ़ाइलें 300 पेज की हों। इंजीनियर साहब आए, चार बार सर्वे हुआ, ठेकेदार ने तीन बार मिट्टी उठवाई, लेकिन बेंच वहीं की वहीं रही–जिस पर बैठना उतना ही साहसिक है जितना चुनाव में खड़े होना। छत का क्या पूछना! वो अब पक्षियों का रिसॉर्ट बन चुका है–कबूतरों की मीटिंग वहीं होती है, और चिड़ियों ने वहाँ 'क्लासिक मल्टीस्टोरी बर्ड हाउस' बसा लिया है। जनता पूछती है–'कहाँ गया पैसा?' तो अफसर मुस्कुराकर कहते हैं, 'जनता के कल्याण में लगा है'–और जनता समझ लेती है कि कल्याण अब किसी मंत्री के दामाद का नाम है।

और इस सब के बीच यात्री–जिसे 'आम आदमी' कहना अब असम्मान लगता है, क्योंकि आम तो अब फल है, आदमी नहीं। वो खड़ा है, बस की ओर आँखें गड़ाए, जैसे कृष्ण के द्वारका लौटने की प्रतीक्षा हो। कोई कहता है, 'बस तो आएगी,' जैसे भगवान के अवतार की भविष्यवाणी कर रहा हो। हर चेहरा थका हुआ है, पर हार नहीं मानी। लड़की अपने मोबाइल में मेट्रो शहरों की सेल्फियाँ देखती है, और पास में एक मजदूर मिट्टी से सनी चप्पलें पहनकर कहता है, 'ये दिल्ली नहीं, लोकतंत्र है!' यहाँ रुकने की वजह कोई सुविधा नहीं–बल्कि आदत है, जैसे नेताओं को वादा करने की।

यह बस स्टॉप नहीं–एक जीवित प्रतीक है हमारे राष्ट्र निर्माण का। यहाँ से कोई कहीं नहीं जाता, लेकिन सब यहाँ से शुरू होते हैं। यह वो जगह है जहाँ देश चलता नहीं, पर ठहर कर सोचता है। और सोचकर भी कुछ नहीं करता। यही हमारी परंपरा है–उम्मीद के साथ जीना, और हर बार बस के आते-आते ये मान लेना कि 'आज नहीं तो कल आएगी।' यही वो लोकतांत्रिक धड़कन है जो न नारों से सुनाई देती है, न योजनाओं से–बल्कि धूल में, पसीने में और उस खाली बेंच में समाई होती है, जो हर बार गिरती है फिर उठती है... जैसे यह देश।

डेंगू, मलेरिया और जीका : खतरनाक कीट, वैश्विक संकट

विश्व मच्छर दिवस पर विशेष

श्वेता गोयल

लेखक शिक्षक हैं।

मच्छर पूरी दुनिया में बीमारियों के सबसे बड़े वाहक होते हैं, जिनके काटने से डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, जीका वायरस इत्यादि जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। डेंगू और मलेरिया इन सभी में सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, जो कई मामलों में जानलेवा साबित होते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 में मच्छरों के काटने के कारण अफ्रीका में सर्वाधिक मौतें हुई थी। दुनिया के कई हिस्सों में मच्छरों के काटने से होने वाली मौतें आज भी गंभीर चिंता का कारण हैं, इसीलिए मच्छरों से होने वाली बीमारियों के प्रति लोगों में जागरुकता फैलाने और बचाव के उपायों के बारे में बताने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 20 अगस्त को एक खास विषय के साथ 'विश्व मच्छर दिवस' मनाया जाता है। 20 अगस्त को ही यह दिवस मनाने का कारण यही है कि 1897 में लिवरपूल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन के ब्रिटिश डॉ. सर रोनाल्ड रॉस ने इसी दिन मादा एनाफिलीज मच्छर की खोज की थी, जिसके काटने से मलेरिया होता है। यह पहली बार था, जब किसी डॉक्टर ने मच्छर और मलेरिया के बीच संबंध स्थापित किया था और उनकी उस खोज ने मलेरिया की रोकथाम और उपचार खोजने में मदद की। मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और मच्छरों के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए 20 अगस्त 1897 से ही इस दिन की शुरुआत हुई। मलेरिया से जुड़ी महत्वपूर्ण खोज के कारण ही डॉ. रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

इस वर्ष 'विश्व मच्छर दिवस' का विषय है 'अधिक समतापूर्ण विश्व के लिए मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई में तेजी लाना' जो विशेष रूप से कमजोर आबादी के लिए मलेरिया की रोकथाम, निदान और उपचार तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देता है। यह मलेरिया नियंत्रण में प्रभावी हस्तक्षेपों को बढ़ाने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। मलेरिया सबसे आम लेकिन जानलेवा वेक्टर जनित बीमारी है, जो संक्रमित मच्छर के काटने से होती है, जिसके माध्यम से परजीवी रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है। यह ऐसी परजीवी बीमारी है, जो अफ्रीका और दक्षिण एशिया जैसे गर्म और आर्द्र जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक आम है। हालांकि समय पर निदान और उपचार जटिलताओं को रोक सकता है तथा कई लोगों की जान बचा सकता है। जब कोई मच्छर मलेरिया से संक्रमित किसी व्यक्ति को काटता है तो वह मच्छर भी संक्रमित हो जाता है, फिर यह संक्रमित मच्छर अपने काटने से परजीवी को स्वस्थ व्यक्ति में फैला सकता है, जिससे बीमारी फैलती है। बता दें कि सभी मच्छर मलेरिया नहीं फैलाते बल्कि केवल संक्रमित मादा एनाफिलीज ही इसे मनुष्यों में फैलाने में सक्षम होते हैं। मलेरिया एनाफिलीज मच्छर से नहीं होता बल्कि ये मच्छर परजीवी का काम करते हैं। यदि कोई मच्छर आपको काटता है और उसमें मलेरिया है तो परजीवी आपके रक्त प्रवाह में चला जाएगा, जो आपके पूरे शरीर को संक्रमित कर सकता है।

वैसे तो दुनिया में मलेरिया का उपचार मच्छर की खोज से पहले भी था। वैज्ञानिकों ने उससे पहले 'कुनैन' दवा की खोज कर ली थी लेकिन उसकी कमी के कारण हर साल हजारों लोगों की जान जा रही थी। 1897 में मलेरिया के वाहक एनाफिलीज मच्छर की खोज होने के बाद ही मलेरिया से निपटने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा कई और महत्वपूर्ण रिसर्च की गई। हालांकि समय के साथ मलेरिया परजीवियों ने आर्टेमिसिनिन और क्लोरोक्वीन सहित आमतौर पर मलेरिया के उपचार में इस्तेमाल की जाने वाली कई दवाओं के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लिया है, इसीलिए अब दुनियाभर के कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ मलेरिया से लड़ने वाली बेहतर दवाओं की खोज जारी रखे हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार मच्छरों से होने वाली बीमारियों के कारण दुनियाभर में हर साल सात लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। मच्छरों के काटने से डेंगू, मलेरिया, जीका वायरस, वेस्ट नाइल, पीला बुखार, लिम्फैटिक फाइलेरिया जैसी बीमारियां होती हैं। मच्छर के काटने पर बहुत ज्यादा खुजली और जलन की समस्या होती है। दुनियाभर में हर साल मलेरिया के करीब 29 करोड़ मामले सामने आते हैं और मलेरिया से प्रतिवर्ष चार लाख से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। हर साल भारत में ही करीब 4 करोड़ लोग मच्छर जनित बीमारियों से प्रभावित होते हैं, जिनमें मलेरिया सबसे आम है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार भारत में मलेरिया के ही प्रतिवर्ष करीब डेढ़ करोड़ मामले सामने आते हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में मलेरिया के मामले रिपोर्ट होते हैं। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक दुनियाभर में मलेरिया के करीब 70 प्रतिशत मामले 11 देशों में ही केंद्रित हैं, जिनमें से एक भारत तथा बाकी अफ्रीकी महाद्वीप के हैं। मलेरिया ऐसी बीमारी है, जो आमतौर पर दुनिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को प्रभावित करती है। मलेरिया एक गंभीर और कभी-कभी ऐसी घातक बीमारी है, जिसके लक्षणों में उच्च बुखार, ठंड लगना, पसीना, सिरदर्द और शरीर में दर्द शामिल होते हैं।

दुनियाभर में मच्छरों की करीब 3700 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 393 प्रजातियां भारत में हैं। ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंडके बाद भारत पांचवां सर्वाधिक मच्छर विविधता वाला देश है। इनमें से मच्छरों की कुछ प्रजातियां ही रोगवाहक होती हैं। मच्छरों की ऐसी ही कुछ विशेष प्रजातियां विभिन्न बीमारियों के प्रसार का कारण बनती हैं, जिनमें मलेरिया के अलावा डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, वेस्ट नाइल वायरस रोग, लिम्फैटिक फाइलेरिया इत्यादि प्रमुख हैं। दुनियाभर में 4 अरब से भी ज्यादा लोग एडीज मच्छर द्वारा फैलने वाले डेंगू के जोखिम वाले क्षेत्रों में रहते हैं। डेंगू बुखार आमतौर पर उष्णकटिबंधीय और उप-उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है, जिसके लक्षणों में उच्च बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों और जोड़ो में दर्द तथा त्वचा पर चकत्ते शामिल हैं। डेंगू बुखार कभी-कभी डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम में बदल सकता है, जो जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। चिकनगुनिया के मामले और प्रकोप अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप तथा हिंद और प्रशांत महासागरों में 100 से भी ज्यादा देशों में सामने आए हैं। चिकनगुनिया भी एडीज मच्छर द्वारा ही फैलता है, जिसके लक्षणों में बुखार, जोड़ो में गंभीर दर्द, और त्वचा पर रैशेज शामिल हैं। चिकनगुनिया का दर्द कई महीनों तक बना रह सकता है, जिससे व्यक्ति की जीवन गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। जीका वायरस भी संक्रमित एडीज प्रजाति के मच्छर के काटने से फैलता है। यह वायरस जीका वायरस से संक्रमित व्यक्ति से उसके यौन साथी में शारीरिक संबंधों के जरिये भी फैल सकता है। गर्भवती महिला से उसके गर्भ में पल रहे बच्चे में भी यह वायरस फैल सकता है। गर्भावस्था के दौरान संक्रमण से कुछ जन्म दोष हो सकते हैं। जीका वायरस रोग के मामले और प्रकोप अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिणी प्रशांत और पश्चिमी प्रशांत के क्षेत्रों में सामने आते रहे हैं। वेस्ट नाइल वायरस रोग अमेरिका सहित दुनिया के कई स्थानों में पाया जाता है, जो मच्छर जनित बीमारी का प्रमुख कारण है। यह क्यूलेक्स मच्छर के माध्यम से फैलता है, जो कभी-कभी एन्सेफलाइटिस और मेनिंजाइटिस जैसी गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया में यह वायरस व्यापक है। बार-बार मच्छरों के काटने से फैलने वाला लिम्फैटिक फाइलेरिया एक ऐसा परजीवी रोग है, जिससे 44 देशों में कम से कम 51 मिलियन लोग संक्रमित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनियाभर में फाइलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर, मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए इनके प्रति सावधानी रखना बेहद जरूरी होता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार मच्छरों से जनित बीमारियों में लापरवाही बरतने से यह जानलेवा साबित हो सकती है। मच्छरजनित बीमारियों से बचने के लिए जरूरी है कि अपने घर के अंदर और आसपास साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें, घर के बाहर कूड़ा-कचरा, गंदगी को जमा न होने दें, बारिश के दिनों में घर से बाहर निकलने से पहले पूरी बाजू वाले कपड़े पहनें, रात में मच्छर नहीं काटें, इसके लिए रिपेलेंट का इस्तेमाल करें।

बहुआयामी सोच के नायक राजीव गांधी

जयंती पर विशेष

चित्रा माली

लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं

भारत में प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को 'सद्भावना दिवस' मनाया जाता है। इस दिन को 'समरसता दिवस' तथा 'राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस' के नाम से भी जाना जाता है। सद्भावना दिवस भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में मनाया जाता है। सद्भावना दिवस के अवसर पर देश के अलग-अलग राज्यों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। सद्भावना दिवस साम्प्रदायिक सद्भाव, शांति और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित हैं। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक और विविधता से भरे देश में सद्भावना दिवस लोगों को भाषाई,क्षेत्रीय और धार्मिक मतभेदों से ऊपर उठकर राष्ट्र की प्रगति के लिए मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वर्ष 1992 से राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार भी प्रदान किया जाता रहा है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने साम्प्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और शांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से मदर टेरेसा,लता मंगेशकर,सुनील दत्त, जगन्नाथ कौल,कपिला वात्स्यानन,एस एन सुब्बाराव, निर्मला देशपांडे,स्वामी अग्निवेश, हेम दत्ता,एन राधाकृष्णन, डीआर मेहता,अमजद अली खान, मुजफ्फर अली,मोहम्मद अज़हरुद्दीन,एम.गोपाला कृष्णा, गोपालकृष्ण गांधी,शुभा मुद्गल, स्पिक मैके, वहीदुन खान और गौतम भाई को नवाजा जा चुका हैं। श्री राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 को पश्चिम बंगाल में थे, जब उनकी मां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके अंगरक्षकों के द्वारा कर दी गई थी। सरदार बूटा सिंह और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ ही घंटों के बाद श्री राजीव गांधी पर प्रधानमंत्री बनने का दबाव बनाया। राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से संसद भंग करने और नए चुनाव कराने को कहा,क्योंकि उस समय लोकसभा ने अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा कर लिया था। राजीव गांधी आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने,जिन्होंने भारतीय संसद के इतिहास में 508 सीटों में से 401 सीटों पर भारी बहुमत से विजय हासिल की। राजीव गांधी ने 31 दिसंबर 1984 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 40 वर्ष की आयु में,वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने।

सत्येंद्र नारायण सिंहा लिखते हैं कि 'भारतीय राजनीति को राजीव गांधी के रूप में अब तक का सबसे युवा प्रधानमंत्री मिला।' इस घटना ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया... उनकी मनमोहक मुस्कान, आकर्षण और शालीनता उनकी बहुमूल्य व्यक्तिगत संपत्ति थी... एक वरिष्ठ विपक्षी सदस्य ने मुझसे बात करते हुए स्वीकार किया कि... वह अपनी इस भावना को छिपा नहीं पाए कि राजीव गांधी विपक्ष के लिए अजेय होंगे। प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के तुरंत बाद, राजीव गांधी ने अकाली दल के नेताओं को रिहा कर दिया,जो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद से जेल में बंद थे। उन्होंने ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन पर से भी प्रतिबंध हटा दिया। प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी ने पहली कार्यवाही जनवरी 1985 में 'दलबदल विरोधी कानून' पारित किया। इस कानून के अनुसार, संसद या विधानसभा का कोई भी निर्वाचित सदस्य अगले चुनाव तक किसी विपक्षी दल में शामिल नहीं हो सकता था। इतिहासकार मनीष तेलीकिचेरला चारी इस कानून को मंत्रियों द्वारा दल बदलकर बहुमत हासिल करने के भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर अंकुश लगाने का एक उपाय बताते हैं। 1980 के दशक के दौरान ऐसे कई दलबदल हुए जब कांग्रेस पार्टी के निर्वाचित नेता विपक्षी दलों में शामिल हो गए। राजीव गांधी ने सत्ता में आते ही अलग से महिला एवं बाल कल्याण विभाग की स्थापना की और लोकसभा में अधिक संख्या में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के प्रयास किए, प्रशासन में उच्च पदों पर महिलाओं को आसीन करवाया,इला भट्ट को राज्यसभा का सदस्य नामित किया तथा स्वरोजगाररत महिलाओं की स्थिति का जायजा लेने के लिए इला भट्ट के ही नेतृत्व में राष्ट्रीय आयोग का गठन किया और राष्ट्रीय महिला परिदृश्य - 2000 तक बनाया गया।

राजीव गांधी के ये सभी कार्य ऐसे थे जिनसे महिलाओं को सरकार के सर्वोच्च स्तर पर एक सहयोगी पुरुष मिला था जो महिलाओं को पुरुषों से कमतर नहीं मानता था। सोच के स्तर की यह भिन्नता उन्हें अन्य नेताओं से अलग स्थापित करती है। श्री राजीव गांधी ने 1985 में मुंबई में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्ण अधिवेशन में 'कांग्रेस संदेश यात्रा' की घोषणा की थी। राष्ट्रीय सेवा दल के द्वारा इसे पूरे देश में चलाया गया तथा प्रदेश कांग्रेस समितियों (पीसीसी) और पार्टी के नेताओं ने मुंबई, कश्मीर, कन्याकुमारी और पूर्वोत्तर से एक साथ चार यात्राएं प्रारंभ कीं। यह यात्रा तीन महीने से अधिक समय तक चली और दिल्ली के रामलीला मैदान में संपन्न हुई। श्री राजीव गांधी ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इनसे संबंधित उद्योगों के लिए सरकारी समर्थन बढ़ाया और प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों,विशेषकर कंप्यूटर, एयरलाइंस,रक्षा और दूरसंचार पर आयात कोटा, कर और शुल्क को कम कर दिया। 1986 में, उन्होंने भारत भर में उच्च शिक्षा कार्यक्रमों को आधुनिक बनाने और विस्तारित करने के लिए शिक्षा पर एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। 1986 में,उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रणाली की स्थापना की,जो एक केंद्र सरकार आधारित शिक्षा संस्थान है जो ग्रामीण आबादी को छठी से बारहवीं कक्षा तक मुफ्त आवासीय शिक्षा प्रदान करता है। उनके प्रयासों से 1986 में एमटीएनएल का निर्माण हुआ और उनके सार्वजनिक कॉल कार्यालयों-जिन्हें पीसीओ के रूप में जाना जाता है - ने ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन नेटवर्क विकसित करने में मदद की।

समाचार वेबसाइट

वन इंडिया के अनुसार 'लगभग 20 साल पहले टेलीफोन को अमीरों के इस्तेमाल की चीज माना जाता था,लेकिन इसे ग्रामीण जनता तक ले जाने का श्रेय राजीव गांधी को जाता है'। श्री राजीव गांधी ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री राजीव गांधी ने जुलाई 1987 में भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में 'तमिल-बहुल क्षेत्रों में सत्ता के हस्तांतरण' की परिकल्पना की गई, लिट्टे को भंग कर दिया गया और तमिल को श्रीलंका की आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया। भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद 30 जुलाई 1987 को विजिथा रोहाना नामक एक सम्मान रक्षक ने अपनी राइफल से श्री राजीव गांधी के कंधे पर वार किया। श्री राजीव गांधी ने बाद में इस घटना के बारे में बताया कि 'जब मैं गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण कर रहा था और एक व्यक्ति के पास से गुज़र रहा था, तो मैंने अपनी आंख के कोने से कुछ हलचल देखी। मैं सहज ही थोड़ा झुक गया। मेरे झुकने से,मेरा सिर से बच गया और वार का ज़ोर मेरे बाएं कान के नीचे कंधे पर लगा। 1990 में श्री राजीव गांधी ने विभिन्न माध्यमों से (पदयात्रा,रेल,बस और कार) 'भारत यात्रा' चंपारण से प्रारंभ की। श्री राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को श्रीपेरंबदूर में लोकसभा कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए हुई थी,जो मद्रास (वर्तमान चेन्नई) से लगभग 40 किलोमीटर (25 मील) दूर का एक गांव है। इस आत्मघाती हमले को लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम (लिट्टे) की सदस्य 22 वर्षीय कलैवानी राजरत्नम (जिसे धनु के नाम से भी जाना जाता है) ने अंजाम दिया था। श्री राजीव गांधी की हत्या के तुरंत बाद, तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने 22 मई 1991 को जांच सीबीआई को सौंप दी थी। एजेंसी ने हत्या के लिए ज़िम्मेदार लोगों का पता लगाने के लिए डॉ. कार्तिकेयन के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। एसआईटी की जांच में श्री राजीव गांधी की हत्या में लिट्टे की भूमिका की पुष्टि की गई थी। जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा। हम अपने लोकप्रिय नायकों को उनके साथ घटी घटनाओं और रची गई साजिशों को लोक माध्यमों के माफ़त लोगों तक प्रेषित करते हैं। इसी क्रम में अभी हाल ही में 4 जुलाई 2025 को सोनी लिव पर The Hunt: The Rajiv Gandhi Assassination Case वेब सीरीज रिलीज हुई थी जो 2022 में प्रकाशित अनिरुधय मित्रा की किताब Ninety Days: The True Story of the Hunt for Rajiv Gandhi's Assassins पर आधारित है। जिसका निर्देशन नागेश कुकुनूर ने किया है। नागेश कुकुनूर ने राजीव गांधी की हत्या को वास्तविक स्थान पर फिल्माने और तथ्यों को जस का तस रखने का ईमानदार प्रयास किया है और जांच के एक एक दिन का ब्यौरा प्रस्तुत किया है। 90 दिन की यह जांच श्री राजीव गांधी के जन्मदिन पर ही समाप्त होती है। उसी के साथ कई सारे प्रश्नों को भी छोड़ती जिनमें से एक आरोपियों तक पहुंचने के बाद भी उन्हें आत्महत्या करने का समय क्यों दिया जाता है? सत्ता परिवर्तन और नौकरशाहों की कार्य प्रक्रिया और निर्देशों के पालन की सीमा और इससे उपजे कई और प्रश्न भी इसमें समाहित है। इसके पूर्व भी श्री राजीव गांधी के जीवन खासकर उनकी हत्या पर केंद्रित कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीस भी बनाई गई हैं। 1991 में सिमी गरेवाल ने एक डॉक्यूमेंट्री टेलीविजन श्रृंखला 'इंडियास राजीव' बनाई थी जो राजीव गांधी की हत्या के तुरंत बाद जारी की गई थी। इस डॉक्यूमेंट्री में राजीव गांधी के जीवन और उनकी हत्या को कवर किया गया है। 1997 में संतोष सीवन ने 'द टेररिस्ट' बनाई थी जो विशेष रूप से राजीव गांधी की हत्या की साजिश पर केंद्रित थी। 2006 में ए.एम.आर रमेश की 'सायनाइट' 2007 में आर.के.सेल्वियामणि की कुटेट्रापथिरिकाई,2007 में ही मेजर रवि की 'मिशन 90 डेज' और 2013 में शूजित सरकार की 'मद्रास कैफे' फिल्म आई थी।

गंगा प्रसाद 'अरुण': भोजपुरी साहित्य का दीपस्तंभ बुझा पर ज्योति शेष है

साहित्यिक

नृपेन्द्र अभिषेक 'नृप'

भोजपुरी साहित्य जगत आज गहरे शोक और स्तब्धता में डूबा हुआ है। जनप्रिय कवि, गीतकार, नवगीतकार, ग़ज़लकार और बहुआयामी साहित्यकार गंगा प्रसाद 'अरुण' (79 वर्ष) के निधन की खबर ने पूरे भोजपुरी समाज को गमगीन कर दिया है। यह केवल एक साहित्यकार का अवसान नहीं है, बल्कि आधी शताब्दी से अधिक समय तक भोजपुरी साहित्य की सेवा करने वाले एक युगप्रवर्तक व्यक्तित्व का जाना है। उनकी लेखनी ने गीतों से लेकर नवगीत, ग़ज़ल और हाइकु तक, हर विधा को समृद्ध किया और उनकी रचनाओं ने भोजपुरी को केवल भाषा भर नहीं, बल्कि संवेदनाओं, लोकजीवन और सांस्कृतिक चेतना की वाहक के रूप में प्रतिष्ठित किया।

गंगा प्रसाद 'अरुण' का साहित्यिक सफर एक सामान्य लेखक से शुरू होकर भोजपुरी साहित्य के स्तंभ पुरुष बनने तक का रहा। वे 1966 में जमशेदपुर भोजपुरी साहित्य परिषद की कार्य समिति के सदस्य चुने गए और तब से लेकर 2013 तक परिषद के प्रवर समिति में सक्रिय रहे। यही नहीं, उन्हें परिषद का आजीवन सदस्य बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। उनके संगठनात्मक कौशल और साहित्यिक दृष्टि का परिणाम था कि 2013 में उन्होंने सिंहभूम जिला भोजपुरी साहित्य परिषद की स्थापना की और इसके संस्थापक अध्यक्ष बने। यद्यपि 2014 में व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने पद त्याग दिया, किंतु स्वतंत्र लेखन और पत्रिका 'लकीर' के प्रकाशन में उनकी सक्रियता पूर्ववत बनी रही।

उनका साहित्यिक व संस्थागत योगदान केवल परिषद तक सीमित नहीं था। वे 'रचनाकार' संस्था के प्रधान सचिव, भोजपुरी जन जागरण अभियान (झारखंड इकाई) के मुख्य संरक्षक, अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन, पटना के कार्य समिति व प्रवर समिति सदस्य तथा जमशेदपुर हिंदी परिषद व बेनीपुरी साहित्य परिषद से भी गहरे जुड़े रहे। यह उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी कि वे साहित्य को केवल व्यक्तिगत साधना न मानकर समाज और भाषा की सामूहिक धरोहर मानते थे।

गंगा प्रसाद 'अरुण' की लेखनी की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे हिंदी और भोजपुरी दोनों में समान अधिकार से लिखते थे। पिछले पाँच दशकों में उनकी रचनाओं ने भोजपुरी साहित्य को न केवल समृद्ध किया, बल्कि उसकी शैक्षणिक प्रतिष्ठा भी बढ़ाई। उनके प्रमुख कृतियों में हहरत हियरा (भोजपुरी गीत संग्रह, 1974), अँगना महुआ झरल (गीत-नवगीत संग्रह, 2010), तीन डेगे त्रिलोक (हाइकु संग्रह, 2013), ग़ज़ल गवाह बनी (ग़ज़ल संग्रह, 2018), प्रेम न बाड़ी ऊपजै (मदन लेख संग्रह, 2020), मनुवा मनगीत लिखे (मनगीत संग्रह, 2021) और द्वंद्व समास (ललित गद्य संग्रह, 2021) विशेष रूप से चर्चित रहे। उनकी कृति अँगना महुआ झरल से सात रचनाएँ बिहार विश्वविद्यालय के एम.ए. भोजपुरी पाठ्यक्रम में शामिल की गईं। इसी तरह उनका यात्रा-वृत्तांत फोकट में सैर भी एम.ए. भोजपुरी पाठ्यक्रम का हिस्सा बना। यह किसी भी लेखक के लिए सम्मान की बात होती है कि उसकी रचनाएँ आने वाली पीढ़ियों के लिए शैक्षणिक सामग्री बनें। उनके अप्रकाशित किंतु तैयार कृतियों में गोड़ में बाँस (ललित गद्य) और अतुकान्तिकाये (स्फुट हिन्दी-भोजपुरी) प्रमुख हैं, जो उनकी सृजनशीलता की अनवरत धारा का प्रमाण है।

अरुण जी की साहित्य सेवा केवल अपनी रचनाओं तक सीमित नहीं थी। उन्होंने लुकार, लकीर, रचनाकार, विकासवार्ता और पर्यावरण चिंतन जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई महत्वपूर्ण स्मारिकाओं का भी संपादन किया, जिनमें जमशेदपुर

भोजपुरी साहित्य परिषद की रजत जयंती और स्वर्ण जयंती स्मारिका तथा अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन की स्मारिका इस्पातीका शामिल हैं। उनके संपादित ग्रंथों में अगुआ, बिना के तान, सुपुली भर तरेगन, फूल हरसिंगार के, हरिशंकर वर्मा स्मृति ग्रंथ और निर्भीक अभिनन्दन-ग्रंथ प्रमुख हैं। इस तरह उन्होंने न केवल अपनी लेखनी से, बल्कि अन्य लेखकों की रचनाओं को मंच और पहचान देकर भी भोजपुरी साहित्य को विस्तार दिया।

गंगा प्रसाद 'अरुण' का व्यक्तित्व केवल किताबों और पत्रिकाओं तक सीमित नहीं था। वे एक सशक्त मंचीय कवि भी थे। बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओड़िशा और दिल्ली के अनेकों मंचों पर उन्होंने सस्वर कविता पाठ किया। 2018 में गणतंत्र दिवस पर दिल्ली सरकार की मैथिली-भोजपुरी अकादमी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में उनका आमंत्रण और कविता पाठ उनके कद का प्रमाण है। उनकी रचनाएँ आकाशवाणी, दूरदर्शन और सहारा समय जैस मंचों से प्रसारित हुईं। विशेषकर उनके लिखे राष्ट्रीय चेतना गीत आकाशवाणी पर वर्षों तक प्रसारित होते रहे, जिन्होंने देश की सामूहिक चेतना को स्वर दिया। मंच पर वे आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री, रामधारी सिंह दिनकर, जनकवि नागार्जुन, काका हाथरसी, हुल्लड़ मुरादाबादी, अज्ञेय, डॉ. रामविचार पाण्डेय और पाण्डेय कपिल जैसे दिग्गजों के साथ साझा कर चुके थे। यह उनके साहित्यिक कद और लोकप्रियता का साक्ष्य है।

गंगा प्रसाद 'अरुण' के साहित्यिक योगदान को समय-समय पर अनेक सम्मान और पुरस्कारों से नवाज़ा गया। उन्हें भिखारी ठाकुर सम्मान, डॉ. प्रभुनाथ सिंह सम्मान, इस्पात भारती सम्मान, साहित्य सेवा सम्मान, अखिल भारतीय भोजपुरी सम्मान, भोजपुरी सेवी सम्मान, संकल्प साहित्य शिरोमणि सम्मान, सरदार पटेल सम्मान, लायन्स क्लब सम्मान, आचार्य महेन्द्र शास्त्री पुरस्कार, विश्व भोजपुरी सम्मेलन सम्मान, भोजपुरी अस्मिता सम्मान और पाती अक्षर सम्मान जैसे अनेकों अलंकरण मिले। ये पुरस्कार केवल औपचारिकता नहीं थे, बल्कि उनके बहुआयामी साहित्यिक व्यक्तित्व की सामाजिक स्वीकृति का प्रतीक थे।

गंगा प्रसाद 'अरुण' केवल कवि और लेखक ही नहीं, बल्कि एक उत्कृष्ट सुलेखक और कला प्रेमी भी थे। कई पत्रिकाओं और पुस्तकों की आवरण सज्जा, प्रमाणपत्र लेखन, अभिनंदन पत्र और हस्त-लेखन उनके द्वारा किया गया। उनकी रचनाओं में जहां संवेदनाओं का प्रगाढ़ संसार मिलता है, वहीं उनकी कला में सौंदर्यबोध की अद्भुत छटा बिखरी रहती थी। आज जब अरुण जी हमारे बीच नहीं हैं, तो भोजपुरी साहित्य अपने एक संवेदनशील और बहुआयामी सृजनशील व्यक्तित्व को खो चुका है। उनका जाना एक गहरे शून्य की तरह है, जिसे भर पाना कठिन होगा। किंतु उनका साहित्यिक योगदान और रचनात्मक धरोहर अमर रहेगी। उन्होंने केवल कविताएँ और गीत ही नहीं लिखे, बल्कि भोजपुरी भाषा की गरिमा को भी स्थापित किया।

भोजपुरी साहित्य के इतिहास में उनका नाम एक ऐसे कवि के रूप में हमेशा याद किया जाएगा, जिसने लोकजीवन की गहराइयों से लेकर राष्ट्रीय चेतना तक को अपनी रचनाओं में पिरोया। उन्होंने साहित्य को अपनी साधना और समाज को अपनी प्रेरणा बनाया। उनके गीतों की गूंज, नवगीतों की संवेदना, ग़ज़लों की मृदुलता और हाइकु की संक्षिप्त गहनता सदैव जीवित रहेगी। गंगा प्रसाद 'अरुण' की विदाई के साथ भोजपुरी साहित्य एक अध्याय अवश्य खोता है, किंतु उनकी रचनाएँ अगली पीढ़ियों के लिए पथप्रदर्शक का कार्य करती रहेंगी। वे अपने पीछे भरा-पूरा परिवार और एक अमूल्य साहित्यिक धरोहर छोड़ गए हैं। यह धरोहर ही उनकी अमरता का प्रमाण बनेगी और आने वाले समय में भोजपुरी साहित्यकारों को प्रेरणा देती रहेगी।

शिक्षा विभाग के जे.डी. ने किया स्कूलों का औचक निरीक्षण

बैतूल। संयुक्त संचालक नर्मदापुरम संभाग डॉ. मनीष वर्मा अपने बैतूल जिले के दो दिवसीय प्रवास पर है। मंगलवार को उन्होंने बैतूल में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं का निरीक्षण किया गया। श्री वर्मा ने मॉडल स्कूल शाहपुर, उमावि बांसपानी, जामठी, अंधारिया एवं ससुंदरा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का केंद्र बिंदु अकादमिक व्यवस्था की समीक्षा रहा। विभिन्न कक्षाओं में जाकर श्री वर्मा ने विभिन्न विषयों में कराये जा रहे अध्यापन की

स्थिति, त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के साथ विभिन्न छात्र कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी ली गई। साथ में छात्र-छात्राओं से सत्यापन भी किया गया। श्री वर्मा ने मुख्यतः विद्यार्थियों से अधिक से अधिक अभ्यास कराए जाने, विशेषकर लिखने का अभ्यास कराया जाने, छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में किए जा रहे कक्षा कार्य एवं गृह कार्य को नियमित रूप से शिक्षकों द्वारा परीक्षण किए जाने, पाठ योजना बनाई जाकर कक्षा शिक्षण किए जाने के बारे में विस्तार से न केवल जानकारी दी गई, बल्कि शिक्षकों को प्रोत्साहित करते हुए उत्कृष्ट परिणाम के लिए प्रेरित किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. अनिल कुशवाहा, विभागीय अधिकारी सुबोध शर्मा, धर्मेंद्र पवार साथ रहे। विकासखंड शिक्षा अधिकारी गुलाबराव बर्ड, धीरेंद्र साहू, सक्षम बारमाते, आशीष शर्मा, बीआरसीसी मनीष धोते, प्राचार्य नागेश पवार, अनिल पाटिल इत्यादि भी अवलोकन दौरान साथ रहे। संयुक्त संचालक का यह दौरा 20 अगस्त को भी जिले में विभिन्न शालाओं में निरंतर रहेगा। निरीक्षण के उपरांत श्री वर्मा द्वारा जिले में विभिन्न शालाओं में अध्ययन अध्यापन की स्थिति को बेहतर पाने पर प्रशंसा भी की गई।

भड़ंगा नदी में पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली, 3 युवक फंसे

पुलिस-ग्रामीणों ने मिलकर किया रेस्क्यू, बचाई जान

बैतूल। चोपना थाना क्षेत्र में भड़ंगा नदी में सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे बटकीडोह और नारायणपुर के बीच भड़ंगा नदी के रपटे पर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पानी के तेज बहाव में पलट गई। ट्रैक्टर में सवार 5 युवकों में से 2 तैरकर बाहर निकल आए, जबकि 3 युवक नदी के बीच फंस गए। डायल-100 को सूचना मिलते ही चोपना टीआई नरेंद्र सिंह

परिहार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एसपी निश्चल झारिया के निर्देश और एसडीओपी सारणी प्रियंका करचाम के मार्गदर्शन में बचाव अभियान शुरू किया गया। पुलिस टीम ने ग्रामीणों की मदद से सुरक्षा उपकरण और रस्सियों का उपयोग कर नदी के बीच करीब 30 मीटर दूर चट्टान तक पहुंचकर तीनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। सभी युवक ग्राम गुवाड़ी के रहने वाले हैं। वे सुरेश उइके, आदित्य उइके, आयुष उइके, पीयूष उइके और शर्मा भलावी हैं। युवक अपने पिता की रिटायरमेंट के बाद घर का सामान सारणी से ले जा रहे थे। रात के समय पानी के तेज बहाव का अंदाजा नहीं लगा पाने के कारण दुर्घटना हो गई। बचाव कार्य में निरीक्षक नरेंद्र सिंह परिहार, सउनि विनोद इवने, आरक्षक विवेक, सुरेंद्र, प्रवेश और डायल-100 चालक गोविंद शामिल थे। ग्रामीणों में रामप्रसाद मंडल, श्रीवास सिकदार, चित्तरंजन सिकदार, दिलीप घरामी, आरती सिकदार और भगवती सिकदार ने मदद की।

सीएमएचओ ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भौंरा और उप स्वास्थ्य केन्द्र कुण्डी का किया औचक निरीक्षण

बैतूल। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज कुमार हुरमाड़े ने सोमवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भौंरा एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र कुण्डी का औचक निरीक्षण किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भौंरा में निरीक्षण के दौरान सायंकालीन ओपीडी,

एएनसी रजिस्टर, लेबररूम रजिस्टर देखा एवं संस्थागत प्रसव की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंलने सभी स्टाफ को निर्धारित समय पर ड्यूटी करने के निर्देश दिए। निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य केन्द्र कुण्डी का निरीक्षण कर उसमें पाई कमियां पूर्ण करने एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र पहावाडी के सामने बनी नाली में वर्षाकाल में अत्याधिक पानी बह रहा था पानी की निकासी की व्यवस्था करने के लिए निर्माण ऐजेन्सी को निर्देश दिए।

अष्टविनायक वेयर हाउस में मूंग खरीदी में हेराफेरी के आरोप, किसानों ने की जांच की मांग

आरोप : तुलवाई गई मूंग को गिरवाकर फिर से बेची

आठनेर/ बैतूल। शासन द्वारा पिछले दिनों समर्थन मूल्य पर की गई मूंग खरीदी को लेकर आठनेर एवं भैंसदेही क्षेत्र के किसानों ने बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। किसानों का आरोप है कि आठनेर से 2 किलोमीटर की दूरी पर बैतूल रोड गुनखेड़ में स्थित अष्ट विनायक वेयर हाऊस को मूंग खरीदी का केन्द्र बनाया गया था, जहां पर मूंग की खरीदी करते समय किसानों से बड़ी धांधली की गई। नियमानुसार किसानों से मूंग की कट्टी का वजन 50 किलो 580 ग्राम तुलवाई के समय होना चाहिए था। इसी मूंग को बोरियों की सिलाई करने से पहले एक से लेकर तीन किलो तक गिरवा दिया गया। बाद में इसी मूंग को जमा कर वेयर हाऊस में तुलवाई कर दी गई। जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। इस तरह 45 किलो से 48 किलो के बीच मूंग तुलवाया गया, जो कि एक तरह से मूंग खरीदी में गड़बड़ी और हेराफेरी को स्पष्ट दशार्ता है। गौरतलब है कि बैतूल जिले में गत् 7 जुलाई से मूंग-उड़द की खरीदी शुरू की गई थी और समर्थन मूल्य में खरीदी के लिए पूरे जिले में 22 केन्द्र बनाये गये थे। जहां इस साल समर्थन मूल्य पर मूंग-उड़द बेचने के लिए कुल 5198 किसानों ने पंजीयन करवाया था और 8 अगस्त तक मूंग की खरीदी की गई थी। आपको बता दें कि इस बार बैतूल जिले में ग्रीष्मकालीन

मूंग 15,900 हेक्टेयर रकबे में बोई गई थी और बड़े पैमानें पर मूंग का उत्पादन भी हुआ है। लेकिन समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी में गड़बड़ी की आशंका के चलते ही किसानों ने हाथ पीछे खींच लिये और आरोप भी लगाए। इधर कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वे इस मामले की उच्चस्तरीय जांच करवायेंगे।

हेराफेरी के लिए घटिया क्वालिटी की खरीद ली मूंग- मंगलवार को सुनवाई में पहुंचे क्षेत्र के किसानों ने आठनेर अष्टविनायक वेयर हाउस में शासन द्वारा निर्धारित मापदंड को पूरी तरह दरकिनार करके मूंग खरीदी करने के आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एफ एक्यू मानक को लागू करने के निर्देश दिए गए थे। जिसमें मूंग की खरीदी के लिए स्पष्ट यह नियम था कि उपज में विजातीय तत्व 2 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जबकि क्षतिग्रस्त दाने 3 प्रतिशत तक ही लिए जाएंगे। आंशिक क्षतिग्रस्त दाने 4 प्रतिशत तक, सिकुड़े या टूटे हुए दाने 3 प्रतिशत और कीट व्याधिग्रस्त दाने भी अधिकतम 4 प्रतिशत तक मान्य रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मूंग में अधिकतम 12 प्रतिशत तक ही नमी स्वीकार की जाएगी। लेकिन अष्ट विनायक वेयर हाऊस पर इन सभी नियमों को पूरी तरह दरकिनार कर खरीदी की गई।

स्टेक नंबर 4 और 8 की जांच की मांग- क्षेत्र के किसानों ने वेयर हाउस में स्टेक नंबर 4 और 8 की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है, ताकि सच सभी के सामने आ सके। किसानों का आरोप है कि प्राइवेट वेयर हाउस पर सरकारी ताले लगे होते है और ताला तभी खुलता है, जब सरकारी कर्मचारी वहां पर मौजूद हो, लेकिन सरकारी चपरासी और वेयर हाउस संचालक द्वारा वेयर हाउस की चाबी लेकर चले जाते थे। और जो मूंग का लॉट रिजेक्ट हो जाता था, तब वे किसानों /व्यापारियो से उसी रिजेक्ट लॉट में एक किलो से लेकर तीन किलो तक अतिरिक्त मूंग तुलवा कर ले लेते थे। जिससे कि वह मूंग, खरीदी में इस तरह की हेराफेरी के काम आ सके। किसानों का कहना है कि अष्ट विनायक वेयर हाऊस की स्टेक नंबर 4 पर रखी मूंग की तुलवाई की जाये तो वह कम निकलेगी, वहीं स्टेक नंबर 8 पर रखी मूंग गुणवत्ताहीन ही निकलेगी। इन दोनो स्टेक की सही जांच की जाये तो मूंग की खरीदी में की गई हेराफेरी का सच सभी के सामने आ जायेगा।

इनका कहना है -

इस मामले की शिकायत भैंसदेही एसडीएम को की गई थी जिस पर उनके द्वारा तहसीलदार से जांच करवाई जा रही है। आपके द्वारा यह मामला संज्ञान में लाया है तो हमारे द्वारा भी समिति प्रभारी से इसकी जांच करवाई जाएगी। मूंग की खरीदी के समय समिति प्रभारी को ही यह जिम्मेदारी दी गई थी कि तुलवाई के दौरान क्वांटिटी पूरी होना चाहिए। साथ ही क्वालिटी की जांच भी सर्वेयर द्वारा की गई थी।

- रामवीर सिंह राजपूत, सहायक संचालक, कृषि विभाग बैतूल

मूंग की क्वालिटी की जांच कर, उसकी खरीदी योग्य गुणवत्ता की जांच करने का कार्य हमारे द्वारा ही किया जाता है, परन्तु यह कार्य समिति प्रबंधक, वेयरहाउस प्रभारी एवं हमारे द्वारा मिलकर किया जाता है।

- गोविंद जीतपुरे, सर्वेयर आठनेर

प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, देवास में नए शिक्षण सत्र की शुरुआत हेतु भव्य दीक्षारंभ समारोह का आयोजन आज

देवास। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, देवास में दिनांक 20 अगस्त 2025 को पद्मश्री डॉ. नेमनाथ जैन ऑडिटोरियम, में प्रातः 10.30 बजे से नए शिक्षण सत्र 25-26 के शुभारंभ पर एक भव्य दीक्षारंभ समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में संस्थान में प्रवेश लेने वाले एमबीए, एमसीए, बीबीए एवं बीसीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया है। यह संस्थान का 24वाँ बैच है। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना ,सरस्वती पूजन एवं राष्ट्रगीत के साथ किया जाएगा। तत्पश्चात संस्थान के निदेशक प्रो. डॉ. आर. के. जैन प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को दीक्षारंभ नवाचार के बारे में बताएंगे। इस अवसर पर विद्यार्थियों को रक्षा सूत्र बाँधकर संस्थान एवं अध्ययन के प्रति जिम्मेदार रहने की शपथ भी दिलाई जाएगी। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ. अनिल बाजपेयी, ग्रुप डायरेक्टर, पीआईएमआर भोपाल ,कर्नल डॉ. वीरेन्द्र मिश्रा, फाउंडर डायरेक्टर, एकेडमी फॉर प्रोफेशनल एम्पावरमेंट एंड एक्सीलेंस , अमर सिंह बघेल, वाइस प्रेसिडेंट, वीई कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड, देवास विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। कार्यक्रम में डॉ. डेविश जैन प्रेसिडेंट, प्रेस्टीज ग्रुप, डिपिन जैन चेयरमैन, पीआईएमआर देवास, डॉ. राजीव रघुवंशी डायरेक्टर एडमिशन, प्रेस्टीज ग्रुप एवं प्रो. डॉ. आशीमा जोशी डेप्युटी डायरेक्टर, पीआईएमआर देवास भी अपनी उपस्थिति से विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करेंगे। कार्यक्रम के कन्वीनर डॉ. योगेन्द्र सिंह रजावत हैं तथा संचालन भाग्यश्री सेंधव द्वारा किया जाएगा।

दो दिवसीय पक्षियों की आकर्षक प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ

देवास। विश्व छायांकन दिवस के मौके पर, देवास के मशहूर फोटोग्राफर मोहन सिंह राजपूत ने मल्हार स्मृति मंदिर परिसर में दो दिवसीय पक्षियों की फोटोग्राफी प्रदर्शनी का आयोजन किया। मंगलवार को शुरू हुई यह खास प्रदर्शनी आज, 20 अगस्त को भी दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल, सभापति रवि जैन एवं विधायक प्रतिनिधि भरत चौधरी ने किया। इस वर्ष की प्रदर्शनी का मुख्य विषय पक्षी हैं, जिसमें मोहन सिंह राजपूत द्वारा खींचे गए विभिन्न पक्षियों के मनमोहक और अद्भुत चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। इस अवसर पर शहर के कई जाने-माने फोटोग्राफर और कलाकार कैलाश सोनी, रईस खान सहित वरिष्ठ भाजपा नेता मदन सिंह धाकड़, राजेश परमार, भगवान सिंह चावड़ा, महेंद्र सिंह राजपूत, गंगा सिंह सोलंकी, चंद्रपाल सिंह सोलंकी, मनोज राजानी, श्रीकांत उपाध्याय, और मुकेश मेहता भी प्रदर्शनी देखने पहुंचे।

डागा हाउस बैतूल में आज मनाई जाएगी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती, दोपहर 1 बजे होगा कार्यक्रम

बैतूल। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं कंप्यूटर क्रांति के जनक स्व.राजीव गांधी की जयंती पर आज 20 अगस्त को जिला कांग्रेस कमेटी बैतूल द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है, जो दोपहर 1 बजे डागा हाउस बैतूल में आयोजित होगा। कार्यक्रम में स्व. राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष निलय डागा की ओर से जारी आमंत्रण में सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित करें। जन्म जयंती कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक शामिल होकर पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी के योगदान को स्मरण करेंगे। राजीव गांधी को देश में सूचना प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर क्रांति का जनक कहा जाता है, जिन्होंने भारत को आधुनिकता की ओर अग्रसर करने में अहम भूमिका निभाई थी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि यह आयोजन पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी के आदर्शों और योगदान को याद करने तथा उनके बताये मार्ग पर चलने का संकल्प लेने का अवसर होगा।

जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का गंभीरता पूर्वक निराकरण किया जाए: सीईओ

जिला पंचायत सीईओ ने जनसुनवाई में सुनी नागरिकों की समस्याएं

बैतूल। मंगलवार को प्रातः 11 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनसुनवाई में जिला पंचायत सीईओ अक्षत जैन ने नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने अनेक समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया। जनसुनवाई में सभी विभागीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। जनसुनवाई में कुल 90 आवेदन प्राप्त हुए। जिला पंचायत सीईओ श्री अक्षत जैन ने जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का निराकरण गंभीरता पूर्वक किए जाने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए। जनसुनवाई में बैतूल तहसील के ग्राम खेड़ली निवासी कृष्ण पाल चौहान ने ग्राम पंचायत में ग्राम सभा आयोजित नहीं किए जाने की शिकायत की। प्राप्त आवेदन पर जिला पंचायत सीईओ श्री जैन ने जनपद पंचायत सीईओ को प्रकरण की जांच कर निराकरण के निर्देश दिए। खंजनपुर निवासी अरविंद मालवीय ने बकाया वेतन दिलाए जाने के लिए आवेदन दिया। जिस पर जिला पंचायत सीईओ श्री जैन ने श्रम विभाग के अधिकारी को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए। बैतूल निवासी प्रमोद कुमार अवस्थी ने मुआवजा वितरण के संबंध में आवेदन दिया। जिस पर जिला पंचायत सीईओ श्री जैन ने बैतूल एसडीएम को प्रकरण की जांच कर निराकरण के निर्देश दिए।

अवैध कॉलोनी निर्माण की जांच के दिए निर्देश- जनसुनवाई में मुलताई निवासी कमलेश डहारे ने जॉइनिंग से संबंधित शिकायत का निरीक्षण शिक्षा विभाग द्वारा नहीं किए जाने के संबंध में आवेदन दिया। प्राप्त आवेदन पर जिला पंचायत सीईओ श्री जैन ने शिक्षा विभाग के डीईओ को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए। मुलताई तहसील के बीरूल बाजार निवासी बाबूराव ने अवैध कॉलोनी निर्माण को लेकर शिकायती आवेदन दिया। जिस पर जिला पंचायत सीईओ श्री जैन ने संबंधित अधिकारी को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए। आमला तहसील के ग्राम डोडावानी निवासी गोवर्धन ने अनावेदकों के विरुद्ध उचित दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के लिए आवेदन दिया। जिस पर जिला पंचायत सीईओ श्री जैन ने आमला तहसीलदार को सिविल न्यायालय के आदेश का अवलोकन कर अग्रिम कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। बैतूल तहसील के ग्राम किला खंडारा निवासी भुनेश्वरी राठौर ने आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिया। जिस पर जिला पंचायत सीईओ श्री जैन ने महिला बाल विकास विभाग के संबंधित अधिकारी को प्रकरण की जांच का निराकरण के निर्देश दिए।

कोई रचना कभी कोई फैसला नहीं देती

इंदौर। विगत दो दशकों में कहानी और उपन्यास ने कई अप्रत्याशित मोड़ लिए हैं यह भारतीय वाग्मय के लिए अभूतपूर्व घटना है। ऐसे बदलाव के मध्य सदा प्रासंगिक रहने वाले विषय पर आया यथार्थपरक संग्रह हिंदी में कथा साहित्य के वर्चस्व की पैरवी करता है। हम सभी जानते हैं हिंदी में कथा साहित्य का बोल बाला रहा तो कमलेश्वर,मोहन राकेश,राजेंद्र यादव धर्मवीर भारती से लेकर से मन्नू भंडारी और मालती जोशी तक यह उनकी कहानियों की प्रासंगिकता का ही प्रभाव था। इस संग्रह की कहानियां भी उसी यथार्थ के प्रासंगिकता की बानगी है। मुझे नहीं लगता कि संग्रह की रचनाएं कोई फैसला देती है बल्कि कोई भी रचना कभी कोई फैसला नहीं देती ये कहानियां किसी अदालती फैंसले से बहुत बड़ी हैं। भारतीय परिवारों में जिस दिन विवाह की असफलता प्रेम की असफलता के रूप में स्वीकार लिया जायेगा उस दिन विवाह विच्छेद जैसी त्रासदी समाप्त हो जाएगी। यह पूरी तरह से मानसिक खुराक का मसला है। यह व्यक्तव्य अग्निधर्मा की संपादक एवं साहित्यकार डॉ शोभा जैन ने अश्विन कुमार दुबे के कहानी संग्रह 'सफल प्रेम विवाह की असफल दाम्पत्य कथाएं' के विमोचन समारोह एवं चर्चा संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि कही। साहित्यकार अंतरा करवड़े ने पुस्तक पर विस्तार से चर्चा करते हुए प्रत्येक कहानी पर टिप्पणी की। कार्यक्रम की अध्यक्षता सूर्यकांत नागर ने की उन्होंने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रेम, प्रेम विवाह, दाम्पत्य जीवन पर विस्तार से विभिन्न पहलुओं पर सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया।

क्षितिज साहित्य संस्था के बैनर तले संपन्न इस कार्यक्रम में संस्था से जुड़े साहित्यकार डॉ योगेंद्रनाथ शुक्ल, प्रभु त्रिवेदी, वसुधा गाडगिल, डॉ शोभा जैन एवं रश्मि चौधरी का उनके मध्यप्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा घोषित सम्मान के लिए सम्मानित किया । सम्मानित किए जाने वाले साहित्यकारों के बारे में ज्योति जैन ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए सम्मान श्रृंखला का संचालन किया ।

इस अवसर पर शहर के संस्था अध्यक्ष सतीश राठी,ज्योति जैन, दीपक गिरकर, सुरेश रायकवार, देवेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रदीप नवीन, सदाशिव कौतुक, डॉ पुरुषोत्तम दुबे, किशन शर्मा कौशल, रघुराज स्वरूप माथुर और नगर के वरिष्ठ साहित्यकार उपस्थित रहे उपस्थित थे। महिलाओं की उपस्थिति इस कार्यक्रम में सर्वाधिक रही। कार्यक्रम का संचालन लेखिका रश्मि चौधरी ने किया। आभार संस्था के कोषाध्यक्ष सुरेश रायकवार ने माना।

श्रद्धांजलि

राजीव खंडेलवाल
(कर सलाहकार एवं पूर्व बैतूल नगर सुधार न्यास अध्यक्ष)

सुभाष आहूजा: लोकसभा में बैतूल के पहले भगवा झंडाबरदार

सूर्यपुत्री मां ताप्ती की उद्गम स्थली और सतपुड़ा की पर्वतमालाओं से घिरी, महाराष्ट्र की सीमा से लगी बैतूल लोकसभा सीट स्वतंत्रता के बाद से ही बनी हुई है। यद्यपि समय-समय पर इसकी सीमाओं में परिवर्तन अवश्य हुए हैं। पहले यह बैतूल -छिंदवाड़ा लोकसभा सीट कहलाती थी। अब बैतूल- हरदा लोकसभा सीट कहलाती है। पहले यह सामान्य सीट थी और 2009 में आरक्षित होकर 'आदिवासी' हो गई। 1952 से लेकर 2024 तक 72 वर्ष के संसदीय सफर में 1977 के पहले तक बैतूल लोकसभा क्षेत्र का कभी भी स्थानीय तो छोड़िए क्षेत्रीय निवासी भी संसद नहीं बन पाया हमेशा नागपुर पहले तीन बार भीखूलाल चांडक फिर दो बार नरेन्द्र कुमार साल्वे सुभाष आहूजा ही ऐसे पहले शख्स थे। आपातकाल के बाद हुए वर्ष 1977 के लोकसभा चुनाव में न केवल पहला स्थानीय सांसद होने का गौरव प्राप्त किया बल्कि कांग्रेस की लगातार जीत के सफर को रोक कर जनता पार्टी जिसके जनसंघ घटक के सदस्य सुभाष आहूजा थे, जो बाद में भाजपा में परिवर्तित हुई, जनता पार्टी तथा आज की भाजपा कहलाने वाली पार्टी के वे प्रथम संसद सदस्य बैतूल लोकसभा के बनेद्य 27 साल की उम्र में हुए लोकसभा के सबसे युवा सदस्य होने का तत्समय का भी रिकॉर्ड उनके नाम से ही है। युवा मोर्चा के वे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे।

मुझे आज भी वे क्षण याद आते हैं, जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई थी। और चुनाव लड़ने के लिए हमारे द्वारा डॉ. त्रिलोकी नाथ भार्गव के घर (हाथी बंगला) बैठक बुलाई गई थी। मात्र 9 लोगों की उपस्थिति में से 7 लोगों ने 'मजबूरी' बताते चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। आपातकाल में मीसा में जेल में रहने वाले सुभाष और मुझसे, बाकी लोगों ने चुनाव लड़ने बाबत तक कहा नहीं था। तब सुभाष भाई ने खड़े होकर कहा यदि कोई तैयार नहीं है और 'बलि का बकरा' ही बनना है, तो मैं तैयार हूं। तब वी के आनंद (हरदा) द्वारा जनता पार्टी के चुनाव चिंह हल पर किसान चुनाव लड़ने के इनकार करने पर सुभाष के साहस और जनसंघ के प्रति उनकी निष्ठा ने बैतूल से पहली बार जनता पार्टी का विजयी झंडा लहराया।

सुभाष भाई के बाद कई चुनाव लड़े हारे भी। लेकिन पार्टी का झंडा व 'दरी के चार कोने' में से एक कोना वे एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा उठाते रहे। जीवन पर्यन्त पार्टी के प्रति उनकी कर्मठता, निष्ठा व सक्रियता बनी रही। एक सांसद पूर्व सांसद अथवा एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक कार्यकर्ता के रूप में, सिपाही के रूप में वह अंतिम समय तक जब तक स्वस्थ रहे, पार्टी संगठन के लिए कार्य करते रहे। 'सत्ता' की भावना से कभी कदम आगे नहीं बढाया ''संगठन ही सर्वोपरि है' यह मूल मंत्र उनकी राजनीति का केन्द्र बिन्दु रहा।

वर्ष 77 के बाद लम्बे समय के बाद वर्ष 89 में बैतूल लोकसभा से भाजपा का झंडा पुनः आरिफ बेग ने फहराया। मैं उनका चुनाव संचालक था। वर्ष 1984 से लेकर 1996 तक लगातार अल्पसंख्यक मुस्मिल गुफराने आजम, असलम शेर खान, आरिफ बेग़ तीनों भोपाल के थे चुनाव जीतकर एकतरफा मुस्लिम रिर्जव सीट बना दी थी। परन्तु वर्ष 1996 में विजय कुमार खंडेलवाल (मुन्नी भैया) ने फिर भाजपा की नींव नये सिरे से रखकर विजय का जो झंडा गाढ़ा व लगातार चार बार लोकसभा चुनाव जीतकर भाजपा की नींव को मजबूत किया। उनकी मृत्यु की पश्चात उनके सुपुत्र हेमंत खंडेलवाल जो वर्तमान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, ने भी उस 'विजय' को बरकरार रखा। तत्पश्चात ज्योति धुर्वे व वर्तमान में केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने लोकसभा में झंडा उठाये हुए है।

निश्चित रूप से आज भाजपा बैतूल संसदीय क्षेत्र में बहुत मजबूत दिख रही है। उसकी प्रथम जीत का स्वाद जिले की जनता को सुभाष आहुजा ने ही दिलवाया था। इस जीत का लगातार स्वाद विजय कुमार खंडेलवाल की 96 की जीत से जो प्रारंभ हुआ है, वह आज तक बदस्तूर जारी है।

उनका परिवार, उनका संसदीय क्षेत्र के नागरिक सिर्फ रिश्तेदार परिवार थे वे सब आज इस दुखद घड़ी में अपने किसी को 'खोने' का भाव यह सूख रहे है। ईश्वर इस दुखद घड़ी में यह दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे। सुभाष भाई को भावपूर्ण श्रंद्धाजलि।

संक्षिप्त समाचार

केन्द्रीय वैज्ञानिक दलो के सदस्यों ने जायजा लिया

विदिशा (निप्र)। विदिशा जिले में असामयिक हुई वर्षा उपरांत रासायनिक दवाईयों के प्रयोग से क्षतिग्रस्त हुई खरीफ फसलों की शिकायते केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान के संज्ञान में आने पर उन्होंने गत दिवस क्षेत्र के भ्रमण के दौरान खेतो में पहुंचकर क्षतिग्रस्त फसलों का जायजा लिया और पीडित किसानो का ढांढस बंधाते हुए कहा कि फसलो की तबाही होने पर नकली दवा कंपनियों पर सख्त कार्यवाही होगी और उन्होंने केन्द्रीय वैज्ञानिक दलो को खेतो में भेजकर क्षतिग्रस्त होने के कारणो का आंकलन कराने से आश्वस्त कराया था। केन्द्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान के निर्देशो के अनुपालन में सोमवार को केन्द्रीय व राज्य स्तरीय कृषि वैज्ञानिक सात सदस्यीय दलो ने छीरखेडा एवं सेमरा में भ्रमण कर पीडित कृषकों के खेतो में पहुंचकर फसलो की क्षति का आंकलन किया है। विदिशा विधायक श्री मुकेश टण्डन ने वैज्ञानिको से कहा कि वे हरेक पीड़ित कृषक के खेत में जरूर पहुंचे और बाजिव वस्तु स्थिति अपनी रिपोर्ट में उल्लेख करें। विधायक श्री टण्डन ने ग्राम छीरखेडा में पीड़ित कृषक श्री भगवान सिंह और श्री उधम सिंह के खेत में कृषि वैज्ञानिको को साथ में लेजाकर सोयाबीन की फसल में हुई क्षति का जायजा लिया है और रासायनिक दवाईयो के प्रभाव से फसल में हुई क्षति तथा असरविहिन दवाओं के विक्रय से पीडित किसानो को राहत दिलाए जाने के तमाम प्रबंध सुनिश्चित कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है। वैज्ञानिक दलो में अटारी आईसीएआर जोन 9 जबलपुर के डायरेक्टर डॉ एसआरके सिंह, डीडब्ल्यूआर जबलपुर के डायरेक्टर डॉ जेएस मिश्रा, रायसेन के कृषि वैज्ञानिक डॉ स्वप्निल दुबे, इन्दौर के कृषि वैज्ञानिक डॉ अरूण शुक्ला तथा एनआईएसआर इन्दौर के डॉ संजीव कुमार, आईआईएसएस भोपाल के डॉ प्रभात त्रिपाठी एवं आईआईएसएस भोपाल के सीनियर साइंटिस्ट डॉ बीपी मीना दल में शामिल है। कृषि वैज्ञानिक दलो के साथ किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक श्री केएस खपडिया समेत विभागीय अन्य अधिकारी तथा खण्ड स्तरीय अधिकारी साथ-साथ मौजूद रहें वहीं पीड़ित कृषकबंधु ने अपनी समस्याओं को सांझा किया है।

अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को सिविल सेवाओं में चयन के लिए प्रोत्साहन हेतु संचालित है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

सीहोर (निप्र)। सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यार्थियों को सिविल सेवा परीक्षाओं में चयन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। जिले के अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा राज्य सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक परीक्षा 2025 में 05 सफल अभ्यार्थियों को एक लाख रूपये की राशि का भुगतान एवं संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक परीक्षा 2025 में सफल हुए 01 अभ्यर्थी को राशि 40 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है। राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षा नीट (हृश्वश्वञ्ज) 2024 में महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन राशि योजना के अंतर्गत मेडिकल कालेज में प्रवेश लेने वाले 09 विद्यार्थियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 में 04 लाख 50 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान कर लाभान्वित किया गया हैं।

तीर्थ दर्शन योजना में तीर्थ यात्री श्री बालाराम और उनकी पत्नी ने पहली बार रामलला और भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए

विदिशा (निप्र)। रुसल्ली गांव निवासी तीर्थ यात्री श्री बालाराम और उनकी पत्नी श्रीमती गुमनी बाई धाकड़ बताया कि हमारी धार्मिक यात्रा पहली थी रामलला और भगवान विश्वनाथ के दर्शन पहली बार किये हैं यह हमारा सौभाग्य है, भगवान ने हमारी इच्छा पूरी कर दी है और यह सब मध्य प्रदेश शासन की तीर्थ दर्शन योजना से संभव हो पाया है। गौरतला हो कि आज काशी अयोध्या (वाराणसी) की तीर्थ यात्रा कर विदिशा जिले के तीर्थयात्री वापस विदिशा लौटे हैं। स्पेशल ट्रेन से यात्री तीर्थ दर्शनों के लिए गए हुए थे संपूर्ण सुविधा तीर दर्शन योजना अंतर्गत तीर्थ यात्रियों को महिया कराई गई थी जिनकी प्रशंसा तीर्थ यात्रियों ने की है। तीर्थ यात्रियों को लाने ले जाने से लेकर रहना और खाना-पीना इत्यादि व्यवस्थाओऔ की पूर्ती सुनिश्चित कराई गई थी।

साइबर सुरक्षा कार्यशाला आयोजित

सतर्कता ही साइबर अपराध से बचाव का कारगर हथियार है : कलेक्टर बालागुरू के.

साइबर विशेषज्ञों ने सरकारी कामकाज में इंटरनेट, सोशल मीडिया के उपयोग और सरकारी एवं निजी डाटा के उपयोग के बारे में जानकारी दी

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. की अध्यक्षता में सायबर सुरक्षा को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की मध्यप्रदेश कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (एमपीसर्ट) के विशेषज्ञों द्वारा साइबर खतरों, सुरक्षा और सरकारी विभागों के डाटा और अपने निजी डाटा को सुरक्षित करने के बारे में विस्तार ने जानकारी दी। कार्यशाला में कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने कहा कि वर्तमान समय में सरकारी कामकाज में इंटरनेट और डिजिटल तकनीक अब हमारी जीवनशैली का महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है। मोबाइल, इंटरनेट, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा और सोशल मीडिया, ये सब अब दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। लेकिन डिजिटल सुविधाओं के साथ साइबर खतरे भी तेजी से बढ़े हैं। हमें जो डिजिटल सुविधा मिलती हैं, वह कभी-कभी चुनौती बन जाती हैं। सायबर अटैक, डिजिटल फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसी कई घटनाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक ऑनलाइन उपयोगकर्ता के लिए जरूरी है कि वह बहुत ही सावधानी और सतर्कता के साथ इन माध्यमों का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि सावधानी में ही सुरक्षा है। इसके साथ ही समय समय पर शासन की अधिकृत संस्थाओं द्वारा जारी की जाने वाली एडवाइजरी का पालन करें। कार्यशाला में बताया गया कि सायबर सुरक्षा कंप्यूटर, नेटवर्क, प्रोग्राम और डेटा को डिजिटल हमलों, चोरी, क्षति या अनाधिकृत पहुंच से बचाने के लिए विभिन्न उपाय, तकनीकियाँ और रणनीतियां शामिल हैं, जिनका उपयोग संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा, डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मध्यप्रदेश कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम MP-CERT का गठन 14 दिसम्बर 2022 को किया गया है। यह टीम राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा के मुद्दों पर त्वरित प्रतिक्रिया देने और रोकथाम के उपायों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। टीम साइबर हमलों के प्रति जागरूकता का प्रसार करने के साथ ही नागरिकों, सरकारी एजेंसियों और अन्य संस्थाओं को सुरक्षा संबंधी सलाह प्रदान करती है। कार्यशाला में एमपी-सर्ट के प्रमुख सलाहकार श्री अंबर पांडे, विधिक सलाहकार श्री योगेश पंडित, श्री मुकुंद सिंह सोलंकी, कुमारी प्रियंका गोस्वामी ने पीपीटी के माध्यम से तकनीकी जानकारी दी। बैठक में जिला पंचायत सीईओ डॉ नेहा जैन, अपर कलेक्टर श्री वृंदावन सिंह, संयुक्त कलेक्टर सुश्री वंदना राजपूत, एसडीएम श्री नितिन टाले, श्री तन्मय वर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती स्वाति मिश्रा, श्री सुधीर कुशवाह सहित सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

प्रशिक्षण की मुख्य रूपरेखा

प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी। इसमें MP-CERT की कार्यप्रणाली और सेवाओं का परिचय, आम नागरिकों के लिए साइबर सुरक्षा से जुड़ी जागरूकता, कार्यालयीन कार्यस्थलों पर साइबर सुरक्षा अपनाने की अनिवार्यता, ज़िला प्रशासन की भूमिका और उनसे अपेक्षित सहयोग जैसे विषय शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही साइबर हमलों से निपटने की व्यावहारिक रणनीतियों, डिजिटल फ्रॉड, फिशिंग, रैंसमवेयर जैसे साइबर खतरों तथा डेटा सुरक्षा से संबंधित तकनीकी जानकारी भी साझा की गयी है।

साइबर फ्रॉड से कैसे बचें

साइबर फ्रॉड से बचने के लिए अनजान स्रोत से आई कोई भी अटैचमेंट कभी न खोलें, मोबाइल में कोई भी APK फाइल तभी इंस्टॉल करें जब वो विश्वसनीय स्रोत से हो, अपने डिवाइस में एंटीवायरस रखें और ऐप्स को आवश्यक अनुमतियाँ ही दें। शंका हो तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें। सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसा साइबर अपराध है जिसमें हैकर तकनीक की बजाय मानव भावनाओं और विश्वास का दुरुपयोग करता है। इसमें अपराधी खुद को पुलिस, बैंक कर्मचारी या सरकारी अधिकारी बताकर कॉल, मैसेज या ईमेल के माध्यम से लोगों से पासवर्ड, ओटीपी या बैंक डिटेल्स जैसी संवेदनशील जानकारी हासिल करते है।

अनजान कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें, ओटीपी पासवर्ड, और पिन कभी साझा न करें, संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, वीडियो कॉल या डॉक्युमेंट पर विश्वास न करें, बैंकिंग या सरकारी जानकारी सीधे ऐप या वेबसाइट से चेक करें, डिजिटल साक्षरता बढ़ाएं और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA ऑन रखें। मजबूत एक्सेस कंट्रोल लागू करें, सभी उपकरणों पर एंटीवायरस और एंटी-मैलवेयर सॉफ़्टवेयर अपडेट करें। सॉफ़्टवेयर और सिस्टम को अपडेट रखें, फायरवॉल और घुसपैठ पहचान/रोकथाम प्रणाली स्थापित करें। अपने लॉगिन के लिए मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। ईमेल संचार और संवेदनशील डेटा को एन्क्रिप्ट करें। सुरक्षित फ़ाइल-शेयरिंग प्रोटोकॉल लागू करें। कार्यस्थल पर व्यक्तिगत उपकरणों के उपयोग को सीमित करें। सभी कर्मचारियों के लिए क्लीन डेस्क और क्लियर स्क्रीन पॉलिसी को बढ़ावा दें।

स्वच्छता के प्रति जागरूकता और युवाओं के जज्बे को देखकर खुश हुए कलेक्टर

कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता प्रातः शहर भ्रमण पर निकले, स्वच्छता कार्यों का लिया जायजा

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने आज रविवार की प्रातः विदिशा नगर में भ्रमण कर साफ-सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सबसे पहले उन्होंने विदिशा के बस स्टैंड क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा किए जा रहे स्वच्छता कार्यों को देखा।

इस दौरान उन्हें शहर के युवा श्री आयुष कटारे और उनके साथियों द्वारा शहर को साफ स्वच्छ रखने की इस मुहिम में शामिल होकर सफाई के लिए किये जा रहे कार्यों को देखा तो उन्होंने युवाओं द्वारा स्वच्छता के क्षेत्र में किया जा रहा है कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनकी हौसला अफजाई किया। कलेक्टर श्री गुप्ता युवाओं का जज्बा देखकर खुश हुए और कहा कि यह देखकर संतोष होता है कि हमारे शहर के युवा जागरूक होकर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि शहर के युवा स्वप्रेरणा से शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में हर रविवार सफाई अभियान चलाते हैं और लोगों को भी सफाई के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सबको अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए जिससे हमारा अपना शहर साफ-स्वच्छ होगा। निरीक्षण के दौरान सब्जी मंडी क्षेत्र में कचरे के ढेर और गंदगी फैली हुई मिली।

सफाई कर्मचारी और जिम्मेदार अमला मौके पर मौजूद नहीं था। वहीं दुकानदारों ने भी सफाई नही होने की शिकायत की तो कलेक्टर ने सफाई व्यवस्थाओं पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि नगर पालिका के कर्मचारी हर वार्ड में तैनात रहते हैं, लेकिन मौके पर अनुपस्थित रहना गंभीर लापरवाही है। उन्होंने नगर पालिका के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर त्वरित कार्यवाही की जाए।

सीहोर सर्किल से निकाले गये पुराने मीटरों में विद्युत चोरी के 256 मामले पकड़े

सीहोर (निप्र)। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा पूरे कंपनी कार्यक्षेत्र में अब तक 3 लाख 35 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित कर दिये गये हैं। स्मार्ट मीटर की स्थापना के दौरान कंपनी द्वारा पुराने मीटरों को बदला जा रहा है और उपभोक्ता परिसरों में नये स्मार्ट मीटर स्थापित किये जा रहे हैं। सीहोर सर्किल में स्मार्ट मीटर की स्थापना के दौरान उपभोक्ता परिसरों से निकाले गये पुराने मीटरों की एनएबीएल लैब में चेकिंग के दौरान चौकाने वाले तथ्य सामने आये हैं। उपभोक्ताओं के परिसर से निकाले गये ऐसे पुराने मीटरों में तकनीकी खराबी कर रेजिस्टेंस या अन्य छेड़छाड़ की गड़बड़ी के 256 मामले पकड़े गये हैं। इन गड़बड़ी वाले आरोपी उपभोक्ताओं पर कंपनी द्वारा 39 लाख से 02 हजार की बिलिंग की गई है जिसमें से 145 मामलों में उपभोक्ताओं द्वारा मीटर में गड़बड़ी की बात स्वीकार कर 11 लाख 37 हजार की राशि कंपनी के खाते में जमा कराई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामले यह रेखांकित करते हैं कि स्मार्ट मीटर प्रभावी है और उसके द्वारा दर्ज खपत भी सटीक है। कंपनी ने यह भी कहा है कि स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य तेजी से जारी है और इस दौरान उपभोक्ता परिसरों के मीटरों की जॉंच और चेकिंग लगातार जारी रहेगी। गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा पूरे कंपनी कार्यक्षेत्र में अब तक 3 लाख 35 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित कर दिये गये हैं। कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं के परिसर से निकाले गये ऐसे 2 हजार 430 मीटरों में तकनीकी खराबी कर रेजिस्टेंस या अन्य छेड़छाड़ की गड़बड़ी पकड़ी गई है। ये गड़बड़ी कंपनी की एनएबीएल मान्यता प्राप्त मीटर टेस्टिंग लैब में पकड़ी गई है।

दस्तक अभियान एवं स्टॉप डायरिया कैंपेन 16 सितंबर तक

सीहोर (निप्र)। शासन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा 16 सितंबर 2025 तक दस्तक अभियान का प्रथम चरण एवं स्टॉप डायरिया कैंपेन चलाया जायेगा। इसके तहत गंभीर कुपोषित एवं उच्च जोखिम वाले नवजात शिशुओं का चिन्हांकन किया जाएगा अभियान के तहत एनीमिया, निमोनिया, डायरिया की जांच एवं पहचान की जाएगी औ और विटामिन ए का अनुपूरण किया जाएगा। चिन्हांकन के पश्चात आवश्यकतानुसार बच्चों को रेफर भी किया जाएगा। अभियान के तहत आमजन को जागरूक किया जाएगा और समुचित शिशु एवं बाल आहार पूर्ति के संबंध में जानकारी दी जाएगी। इस अभियान का प्रथम चरण गृह भेंट आधारित नहीं होगा यह सेवाएं आंगनबाडी केन्द्र पर संचालित की जाएगी एवं मॉप-अप दिवस में छूटे हुये बच्चों को गृह भेंट कर सेवाएँ दी जायेंगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आमजन से अपील की गई है कि अभियान के तहत अपने पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों को नजदीकी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लेकर जांए और अभियान के तहत स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करें।

प्रदेश के स्कूलों में ही बनेंगे विद्यार्थियों के आधार कार्ड

आधार कार्ड के लिए चलेगा विशेष अभियान

सीहोर (निप्र)। प्रदेश में स्कूल के बच्चों के आधार कार्ड तैयार करने के लिये स्कूल में ही विशेष अभियान 18 अगस्त 2025 से चलाया जायेगा। इसके लिये स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य शिक्षा केन्द्र ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ समन्वय किया है। सरकारी स्कूलों में छात्रों की सुविधा के लिए आधार नामांकन और अपडेट शिविर लगाये जायेंगे। इस अभियान का नाम होगा विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार'। यह पहल मुख्य रूप से बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) पर केंद्रित है। इसमें उनके आधार में उंगलियों के निशान, आईरिस स्कैन और एक तस्वीर अपडेट करना शामिल है। पहला अपडेट तब आवश्यक है जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाए। पहला एमबीयू 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच पूरा होने पर निःशुल्क रखा गया है। विद्यार्थी के उम्र 7 वर्ष की आयु से अधिक होने के बाद शुल्क लागू होगा। दूसरा एमबीयू तब आवश्यक है जब विद्यार्थी 15 वर्ष का हो जाएगा। तीसरा एमबीयू 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच पूरा होने पर निःशुल्क है, लेकिन 17 वर्ष की आयु के बाद शुल्क लागू होगा।

उल्लेखनीय है कि, अपडेटेड बायोमेट्रिक्स वाला आधार कार्ड, स्कूल प्रवेश, प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्ति और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजनाओं जैसी सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए सरकार समयबद्ध तरीके से विद्यार्थियों की 100 प्रतिशत आपार आईडी बनाने का भी लक्ष्य रख रही है। आपार आईडी विद्यार्थियों को उनके सभी शैक्षणिक क्रेडिट, जैसे स्कोर कार्ड, मार्कशीट, ग्रेड शीट, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और सह-पाठ्यचर्या संबंधी उपलब्धियों को डिजिटल रूप से संग्रहीत, प्रबंधित और एक्सेस करने में मदद करती है। यह आईडी शिक्षा जगत में छात्र के लिए एक स्थायी डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करती है। आपार आईडी के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कूलों द्वारा आपार आईडी बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले छ्वद्बस्श्व+ पोर्टल में दर्ज छात्र का नाम, आधार कार्ड में दर्ज नाम से मेल खाना चाहिए। इस संबंध में संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र श्री हरजिंदर सिंह ने बताया कि, ÷विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में आधार शिविर, न केवल छात्रों को अपना अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट करवाने में सुविधा प्रदान करेंगे, बल्कि यदि आवश्यक हो तो आधार में नाम सुधार आपार आईडी बनाने के लिए और मोबाइल नंबर अपडेट के लिए भी उन्हें सुविधा प्रदान करेंगे।

संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र ने बताया कि, 18 अगस्त से प्रारंभ होने वाला अभियान का पहला चरण, मध्यप्रदेश के 40 जिलों में एक साथ शुरू होगा और एक से दो महीने तक चलेगा। आधार शिविरों की प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए (यूआईडीएआई) ने जिलों में उन पिन कोडों की पहचान की है जहाँ सबसे ज़्यादा एमबीयू लंबित हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग ने मुख्य रूप से इन पिन कोडों के अंतर्गत आने वाले सरकारी स्कूलों को शिविरों के लिए चुना है। शेष 15 जिलों में दूसरा चरण सितंबर 2025 के पहले सप्ताह में शुरू होगा। स्थानीय जिला प्रशासन को अपने-अपने जिलों में आधार शिविर योजना का व्यापक प्रचार करने के लिए कहा गया है। अभिभावकों में प्रचार-प्रसार होने से विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार अभियान को सफलता मिलेगी और अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री की घोषणा पर कलेक्टर के निर्देशन में महलपुर पाठा में भव्य श्रीकृष्ण मंदिर के निर्माण हेतु कार्यवाही प्रारंभ

महलपुर पाठा पहुंचकर अधिकारियों ने तैयार किया प्रथम स्तरीय प्राक्कलन

रायसेन (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा जिले के ग्राम महलपुर पाठा में गत दिवस आयोजित कार्यक्रम में महलपुर पाठा में स्थित भगवान श्रीकृष्ण के प्राचीन मंदिर को भव्य स्वरूप देने मंदिर निर्माण संबंधी की गई घोषणा को अमलीजामा पहनाने जिला प्रशासन ने तत्परता से कार्य शुरू कर दिया है। कलेक्टर श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशानुसार घोषणा के अगले ही दिन रविवार को लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री (भवन) और प्रशासनिक अधिकारी महलपुर पाठा पहुंचे और प्राचीन मंदिर को भव्य स्वरूप देने प्रथम स्तरीय प्राक्कलन तैयार किया गया।

अधिकारियों द्वारा प्राचीन मंदिर तथा आसपास के स्थलों का भ्रमण किया गया और मंदिर के पुजारी जी और ग्राम के वरिष्ठजनों से भी भगवान श्रीकृष्ण के भव्य मंदिर निर्माण की रूपरेखा के संबंध में चर्चा की। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जन्माष्टमी पर रायसेन जिले के ग्राम महलपुर पाठा में आयोजित 'श्रीकृष्ण पर्व'- हलधर महोत्सव एवं लीला पुरुषोत्तम का प्रकटोत्सव और लोकार्पण-शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान भगवान श्रीकृष्ण के प्राचीन मंदिर को भव्य मंदिर बनाने की घोषणा की थी। महलपुर पाठा में स्थित 13वीं शताब्दी में निर्मित यह ऐसा मंदिर है जहां राधा-कृष्ण और देवी रुक्मणि की मूर्ति एक ही श्वेत पत्थर पर बनी हुई है। इस मंदिर पर लगा एक शिलालेख इसके संवत 1354 अर्थात वर्ष 1297 ई में निर्मित किए जाने की जानकारी देता है। मंदिर के पास ही प्राचीन किला भी है, जहां परमार वंश के राजाओं का शासन रहा।

मकर संक्रांति पर यहां बड़ा मेला भी लगता है

राधा-कृष्ण मंदिर भी उसी काल का है। साथ ही मकर संक्रांति पर यहां बड़ा मेला भी लगता है। यहां विष्णु यज्ञ भी होता है। मंदिर के पास स्थित किले में 51 बावड़ियां हैं। पास के जंगल से जैन परंपरा के भगवान आदिनाथ की मूर्ति मिली थी जो अब देवनगर में स्थापित है। मंदिर के पास में शिवलिंग, नंदी, गणेश और नाग देवता सहित नटराज की मूर्तियां हैं।

प्रभारी मंत्री समस्याओं से अवगत हुए

विदिशा (निप्र)। पशुपालन एवं डेयरी स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री लखन पटेल ने सोमवार को विदिशा जिले के संक्षिप्त प्रवास के दौरान स्थानीय विधायक श्री मुकेश टण्डन समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने सौजन्य भेंटकर जिले की प्रमुख समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया। प्रभारी मंत्री श्री पटेल को जिले में खरीफ फसलो के उपयोग में लाई गई रासायनिक दवाओं से हुई क्षति के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। नकली कीटनाशक दवा कंपनी पर कार्यवाही करने हेतु केन्द्रीय मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशो से विदिशा विधायक श्री मुकेश टण्डन ने अवगत कराते हुए केन्द्रीय मंत्री के प्रवास दौरान पीडित किसानो से हुए संवाद की जानकारियां सांझा की है। प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने आश्वस्त कराया कि राज्य सरकार किसानो के साथ सदैव है पीड़ित किसानो को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। नियमानुसार कृषि वैज्ञानिकों का दल आज भ्रमण कर अपनी रिपोर्ट देगा तदा नियमानुसार राहत राशि सहित अन्य कार्यवाहियां संपादित की जाएगी। निजी गार्डन में इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ जिला पंचायत सीईओ श्री ओपी सनोड़िया समेत विभिन्न विभागो के अधिकारी, गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

इंदौर से भोपाल के बीच 6 हजार करोड़ की लागत से ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनेगा

केंद्र से सैद्धांतिक मंजूरी, दूरी घटेगी, औद्योगिक विकास को गति मिलेगी

इंदौर। इंदौर से भोपाल के बीच लगातार यात्रा करने वालों के लिए यह बड़ी राहत वाली खबर है। दोनों शहरों को जोड़ने के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे कॉरिडोर बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी। इसके निर्माण के बाद दोनों शहरों के बीच की दूरी 35-40 किलोमीटर तक कम हो जाएगी और अभी लगने वाला 4.30 घंटे का सफर घटकर महज 3 घंटे में पूरा होगा। करीब 6 हजार करोड़ की लागत से बनने वाला यह कॉरिडोर वेस्टर्न भोपाल बायपास के जंक्शन या रातीबड़ के पास से होकर निकलेगा। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने इस एक्सप्रेस-वे को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने इसकी ट्रैफिक स्टडी रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसमें करीब 30 हजार पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) का अनुमान जताया गया है। एक्सप्रेस-वे 8 लेन का होगा और इसमें प्रवेश के लिए तीन स्थानों पर एक्सेस कंट्रोल की सुविधा रहेगी। इसके लिए नीलबढ़ से चापड़ा रोड, मंडीदीप से कसरावद और मंडीदीप से इंदौर वेस्टर्न बायपास तक तीन रूट प्रस्तावित हैं। अधिकारियों के अनुसार इस कॉरिडोर से न केवल ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी में सुधार होगा, बल्कि इंदौर और भोपाल के बीच औद्योगिक विकास भी तेज होगा। इसके किनारे मल्टी लॉजिस्टिक वेयरहाउस और इंडस्ट्रियल हब विकसित किए जाएंगे। करीब 170 से 200 किमी लंबे इस एक्सप्रेस-वे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। उम्मीद है कि इसका निर्माण सिंहस्थ से पहले पूरा हो जाएगा। इससे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दक्षिणी राज्यों के ट्रैफिक को बेहतर ढंग से डायवर्ट और नियंत्रित किया जा सकेगा। एनएचएआई भोपाल के रीजनल ऑफिसर एसके सिंह ने बताया कि तीनों रूट प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे। मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू होगा। इस प्रोजेक्ट से यात्रियों और वाहन चालकों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

भोपाल में देर शाम हुई झमाझम बारिश, बैतूल की भड़ंगा नदी में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी

भोपाल (नप्र)। बारिश के स्ट्रॉन्ग सिस्टम की वजह से अगस्त महीने के आखिरी दिनों में पूरा मध्यप्रदेश भीगेगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में ज्यादा असर देखने को मिला। यहां 21 अगस्त से अति भारी बारिश का अलर्ट है। इससे पहले भी बारिश का दौर चल रहा है। आज मंगलवार को भोपाल समेत कई जिलों में बारिश हुई।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे में आलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा में भारी बारिश हो सकती है। यहां साढ़े 4 इंच तक पानी गिरने का अनुमान है। इसके बाद सिस्टम और स्ट्रॉन्ग होगा। 21 और

22 अगस्त को दक्षिणी और पूर्वी हिस्सा तरबतर हो जाएगा।

खरगोन जिले में रुक-रुककर हो रही बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं। जिले का सबसे बड़ा देजला देवाड़ा जलाशय इस सीजन में पहली बार ओवरफ्लो हुआ। सोमवार देर शाम से पानी जलाशय की स्पील से बाहर छलक रहा है।

नदी में ट्रॉली पलटी, चट्टान में फंसे 3 युवक- बैतूल के चोपना थाना क्षेत्र में भड़ंगा नदी में सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे बटकीडोह-नारायणपुर के बीच भड़ंगा नदी के रपटे पर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पानी के तेज बहाव में पलट गई। ट्रॉली पर सवार 5 युवकों में से 2 तैरकर बाहर निकल आए, जबकि 3 युवक नदी के बीच चट्टान पर फंस गए।

सूचना मिलते ही चोपना टीआई नरेंद्र सिंह परिहार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू कराया। ग्रामीणों की मदद से सुरक्षा उपकरण और रस्सियों का इस्तेमाल कर नदी के बीच करीब 30 मीटर दूर चट्टान तक पहुंचकर तीनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

वर्ष 2024-25 में प्रदेश ने किया 66 हजार 218 करोड़ रूपए का निर्यात

आगामी डेढ़ माह में 5.60 लाख मेट्रिक टन यूरिया प्राप्त होने की संभावना : मुख्यमंत्री

पूंजीगत व्यय में मध्यप्रदेश देश के प्रथम तीन राज्यों में शामिल

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में पूंजीगत व्यय में वृद्धि वाले प्रथम तीन राज्यों में मध्यप्रदेश ने अपना स्थान बनाया है। कैग के आंकड़ों के अनुसार देश के 16 राज्यों ने पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय में वृद्धि दर्ज की है। गुजरात 65 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश 42 प्रतिशत और मध्यप्रदेश की उपलब्धि 41 प्रतिशत है। साल दर साल वृद्धि के साथ मध्यप्रदेश का यह सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश की इस उपलब्धि के लिए मंत्रि-परिषद के सभी साथियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से नई दिल्ली में भेंट कर उन्हें प्रदेश में जारी विकास कार्यों से अवगत कराया तथा उन्हें आगामी दिनों में भोपाल मेट्रो ट्रेन के शुभारंभ और विशाल किसान सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी के दोनों कार्यक्रमों में शामिल होने की संभावना है।

फार्मास्युटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स और सोया उत्पादों के निर्यात बढ़ने से हुई 6 प्रतिशत की वृद्धि

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में मध्यप्रदेश ने निर्यात में अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए अब तक का सबसे अधिक 66 हजार 218 करोड़ रुपए का निर्यात किया है। निर्यात में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो फार्मास्युटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स और सोया उत्पादों में निर्यात बढ़ने के फलस्वरुप हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात में मध्य प्रदेश की रैंकिंग 15 से 11 हो गई है।

स्वतंत्रता दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रमों में हुए नवाचार को मंत्रि-परिषद ने सराहा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम पर किए गए नवाचार के संबंध में मंत्री साथियों से फीडबैक प्राप्त किया। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सभी जिलों में एलईडी के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। साथ ही सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन में संबंधित जिले में विगत डेढ-पौने दो वर्षों में किए गए विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं की प्रगति से जिले वालों को अवगत कराया।

विकसित भारत रोजगार योजना से प्रदेश की औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मंत्रि-परिषद ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू करने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार माना। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इसमें निजी क्षेत्र में नौकरी पाने वाले युवाओं को 15 हजार रूपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे। देश में 3 करोड़ 50 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस योजना से राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हर्ष का विषय है कि इस दीपावली पर देश को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। नई जनरेशन के लिए जीएसटी रिफॉर्म लागू किए जाएंगे। इससे दैनिक उपयोग की चीजें सस्ती होंगी और टैक्स में भी कमी आएगी।

आगामी डेढ़ माह में 5.60 लाख मेट्रिक टन यूरिया प्राप्त होने की संभावना

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि यूरिया का कुल भंडारण 15.60 लाख मेट्रिक टन है, जिसमें से 13.92 लाख मेट्रिक टन किसानों को वितरित किया गया है और 1.68 लाख मेट्रिक टन यूरिया शेष है। प्रदेश में मक्का का क्षेत्रफल लगभग 5 लाख हेक्टेयर बढ़ जाने के कारण यूरिया की मांग बढ़ी है। आगामी डेढ़ माह में 5.60 लाख मेट्रिक टन यूरिया प्राप्त होने की संभावना है।

अलग-अलग थीम पर निकली श्रीमहाकाल की सवारियां

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस वर्ष भगवान श्री महाकाल की सवारियों में नवाचार करते हुए प्रत्येक सवारी एक अलग थीम पर निकाली गई। पहली सवारी जहां वैदिक उद्घोष के साथ निकली वहीं बाद की सवारियां लोक, संस्कृति, पर्यटन आदि पर केन्द्रित रही। सवारियों में प्रदेश के जनजातीय अंचलों के कलाकारों ने पूरे उत्साह से भाग लिया। राजसी सवारी के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की गई, जिसमें सम्पूर्ण नगर से जनभागीदारी के माध्यम से पुष्प एकत्रित किए गए।

स्वदेशी को प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्तमान वैश्विक संदर्भ में देश को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिये प्रधानमंत्री श्री मोदी की दृढ़ता हम सबके लिये प्रेरणा स्त्रोत है। प्रदेश के रायसेन जिले के उमरिया गांव में गत दिनों बीईएमएल आधुनिक रेल कोच कारखाने का शिलान्यास प्रदेश के लिये एक बड़ी सौगात है और स्वदेशी अभियान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी तरह धार जिले में पीएम मित्रा पार्क से मध्यप्रदेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 'फार्म-टू-फॉरेन' की नई दिशा मिलेगी।

एनएसयूआई का डीईओ कार्यालय पर प्रदर्शन

एनसीईआरटी की प्रतियां जलाई

भोपाल (नप्र)। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने मंगलवार को राजधानी में जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित नए मॉड्यूल यानी सिलेबस में कई आपत्तिजनक और भ्रामक तथ्यों को शामिल किया गया है।

प्रस्तुति न केवल कांग्रेस की स्वतंत्रता आंदोलन में निभाई गई ऐतिहासिक भूमिका को कलंकित करती है, बल्कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की छवि को भी धूमिल करती है।

प्रदेश सचिव सैयद अल्तमस ने कहा कि शिक्षा

एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने कहा कि एनसीईआरटी मॉड्यूल में भारत विभाजन से जुड़े तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया गया है। इसमें विभाजन की पूरी जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर थोपने का प्रयास किया गया है। जो कि ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत, पक्षपातपूर्ण और भ्रामक है, भारत का विभाजन कई जटिल कारणों और परिस्थितियों की उपज था। इसे केवल एक राजनीतिक दल पर थोपना सरासर अन्याय है।

निदेशक के नाम सौंपा ज्ञापन- एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर ने कहा कि एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी के सामने मॉड्यूल की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया। जिला शिक्षा अधिकारी को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के निदेशक के नाम ज्ञापन सौंपा है ।

इससे महात्मा गांधी की छवि धूमिल- एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष वरुण कुलकर्णी ने कहा कि ने इस प्रकार की सामग्री का उद्देश्य बच्चों और विद्यार्थियों को तथ्यों पर आधारित सच्चाई बताना होना चाहिए, न कि राजनीतिक पूर्वाग्रह थोपना, छात्र छात्राओं को भ्रमित करने का भाजपा सरकार निरंतर प्रयास कर रहीं लेकिन हम होने नहीं देंगे ।

एनएसयूआई की मांगें

1. एनसीईआरटी मॉड्यूल से आपत्तिजनक और भ्रामक सामग्री को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए।
2. इस प्रकार की गलत जानकारी शामिल करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं विशेषज्ञों पर कड़ी कार्रवाई हो।
3. शैक्षणिक सामग्री का फिर परीक्षण करने के लिए निष्पक्ष और प्रामाणिक इतिहासकारों की एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए।
4. विद्यार्थियों को सत्य और तथ्यों पर आधारित निष्पक्ष इतिहास उपलब्ध कराया जाए ताकि उनकी सोच पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक प्रभाव न पड़े।

भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर एफआईआर के निर्देश

फर्जी दस्तावेजों से कॉलेज की मान्यता लेने के आरोप; हाईकोर्ट ने एसआईटी जांच के दिए आदेश

जबलपुर (नप्र)। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सोमवार को फर्जी दस्तावेजों के जरिए कॉलेज की मान्यता के मामले में सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने कहा है कि भोपाल कमिश्नर तीन दिन में एफआईआर दर्ज करवाते हुए उसकी जानकारी भी कोर्ट को दें।

जस्टिस अतुल श्रीधरन की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पाया कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने फर्जी दस्तावेजों से कॉलेज की मान्यता ली थी। इस मामले पर हाईकोर्ट ने आरिफ मसूद के इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज में नए

दाखिलों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।

एसआईटी करेगी मामले की जांच- हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि इस पूरे मामले की अब एसआईटी जांच करेगी। एडीजी संजीव शमी के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम जांच करेगी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि 90 दिन में एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट पेश करें।

बता दें कि पिछले दिनों उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया था, लेकिन छात्र हित को देखते हुए कॉलेज में छात्रों की पढ़ाई को कंटिन्यू रखा गया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण इतने सालों तक कॉलेज नहीं चल सकता था।

कॉलेज की संचालन समिति में सचिव हैं आरिफ मसूद

इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज का संचालन अमन एजुकेशन सोसाइटी करती है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद इस सोसाइटी के सचिव हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज भोपाल के खानूगांव में स्थित है।

पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह ने की थी शिकायत

पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह ने इस पूरे मामले की शिकायत की थी। जांच के बाद आयुक्त उच्च शिक्षा ने माना कि अमन एजुकेशन सोसायटी ने इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज के संचालन के लिए फर्जी दस्तावेजों पर एनओसी और मान्यता ली। इसके बाद कॉलेज की मान्यता रद्द की गई। जांच में पता चला कि कूटरचित दस्तावेजों के जरिये सेल डीड तैयार करवाई और इसे पंजीयन कार्यालय में फर्जी तरीके से दर्ज भी बताया गया।

निगम-मंडल में नियुक्तियों के कयास हुए तेज

मुख्य सचिव पद पर एक्सटेंशन की अटकलों के बीच राज्यपाल से मिले सीएम अनुराग जैन

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में नए प्रशासनिक मुखिया की तलाश के बीच मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मुलाकात की। इस मुलाकात को मुख्य सचिव जैन के एक्सटेंशन और प्रदेश के निगम मंडलों में होने वाली नियुक्तियों से जोड़ा जा रहा है। जैन का कार्यकाल 31 अगस्त को खत्म हो रहा है।

एक सितम्बर से प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में अनुराग जैन केंद्र से मिलने वाले एक्सटेंशन के रूप में काम करेंगे या इसके लिए एमपी कैडर के वर्तमान सीनियर आईएएस अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसको लेकर अब मंत्रालय और आईएएस लॉबी में सुगबुगाहट का दौर तेज हो गया है।

जैन को एक्सटेंशन मिलने की उम्मीद के चलते सीनियर अफसर अभी इस मामले में खुलकर सामने नहीं आए हैं लेकिन इस बात के लिए जोर आजमाइश जारी है कि अगर जैन को रिटायरमेंट दिया जाता है तो नए मुख्य सचिव के लिए दावेदार अपना नाम आगे बढ़ा सकें।

40 मिनट तक बंद कमरे में की चर्चा

मुख्य सचिव अनुराग जैन सोमवार को दोपहर में राजभवन पहुंचे और राज्यपाल मंगुभाई पटेल से 40 मिनट से अधिक समय तक बंद कमरे में चर्चा की है। बताया जाता है कि जैन ने प्रदेश के प्रशासनिक कामकाज और कानून व्यवस्था की जानकारी देने के साथ ही राज्यपाल पटेल से अपने कार्यकाल को लेकर भी चर्चा की है। हालांकि जैन को एक्सटेंशन देने का फैसला केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को करना है। इसमें राज्यपाल का सीधे तौर पर कोई रोल नहीं है, लेकिन इस मुलाकात को इससे भी जोड़ा जा रहा है।

लव जिहाद और ड्रग माफिया पर कसेंगे शिकंजा, अपराधियों को लगाएंगे ठिकाने : मुख्यमंत्री

हुजूर क्षेत्र में 200 करोड़ के सीवर लाइन सहित अन्य अधोसंरचनात्मक कार्य होंगे

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि महिलाओं पर कुदृष्टि डालने वाले, ड्रग माफिया और लव जिहादियों को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ा जाएगा। लव जिहाद हो या ड्रग माफिया, इनके माध्यम से जो भी आपराधिक गतिविधियां की जा रही हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए शिकंजा कसा जा रहा है। राज्य सरकार किसी अपराधी को छोड़ने वाली नहीं है। सबको एक-एक कर ठिकाने लगाएंगे। सभी प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाते हुए बहन-बेटियों को हर संभव सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को नर्मदापुरम रोड स्थित आमिर मैजेस्टिक पार्क में आयोजित रक्षाबंधन महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बहनों से राखियां भी बंधवाईं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है। रक्षाबंधन से पहले बहनों को लाड़ली बहना योजना की मासिक किश्त सहित 250 रुपए का शगुन अलग से भेजा गया है। बहनों के हाथ में यश होता है, लक्ष्मी पूजन भी उन्हीं के माध्यम से होता है। अब दीपावली के बाद भाई-दूज से प्रदेश भर की लाड़ली बहनों को हर महीने 1500 रुपए की सौगात मिलेगी। बहनों का स्नेह मेरे जीवन का सबसे बड़ा आधार है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव को बहनों की ओर से बड़ी राखी भेंट की गई, इसके बाद अनेक लाड़ली बहनों ने उन्हें राखियां बांधीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी बहनों का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि बहनों के साथ बैठने से माता और पिता दोनों का प्रेम एक साथ मिल जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। परिवार में बहन-भाई का रिश्ता युगों-युगों से अटूट है। महाभारत काल में भगवान श्रीकृष्ण और द्रोपदी का रिश्ता भाई-

प्रदेश की बहनों का स्नेह जीवन का सबसे बड़ा आधार

बहन के प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राजधानी भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ की लागत से सीवर लाइन सहित अन्य विकास कार्य किए जाएंगे। स्थानीय विधायक एवं पूर्व प्रोटेम स्पीकर श्री रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव बेटियों की सुरक्षा और लाड़ली बहनों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेशभर की बहनों ने अपने भाई और मुख्यमंत्री को राखी बांधी है।

राज्य सरकार बहनों को शीघ्र ही, दीपावली भाईदूज से लाड़ली बहन योजना में 1500 रूपये मासिक की राशि देना प्रारंभ करेगी।

शासकीय सेवाओं में मध्यप्रदेश सरकार बहनों को 35 प्रतिशत आरक्षण दे रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोकसभा विधानसभा सहित अन्य संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब हमारी बहनें विधायक, सांसद ही नहीं अन्य पदों पर भी निर्वाचित होंगी।

देवी अहिल्याबाई होल्कर, वीरांगना रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी कमलापति हमारे समाज में साहस शौर्य और सुशासन की प्रतीक हैं।

उद्योगों में काम करने वाली बहनों को विशेष रूप से गारमेंट जैसे रोजगार परक उद्योग में कार्यरत बहनों को 5 हजार प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है।

हाल ही में रक्षाबंधन पर बहनों को 250 रूपए शगुन की राशि भी प्रदान की गई।